Ranchi ● Thursday, 30 January 2025 ● Year : 03 ● Issue : 17 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Daily

THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज़

Published from Ranchi

महाकुंभ में भगदड़ से कई लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना

PRAYAGRAJ @ PTI : बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर 13 अखाड़ों सहित करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में महाकुंभ के संगम तट पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। संगम क्षेत्र में तड़के पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में मरने वालों की संख्या के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे रही। घटना के 17 घंटे बाद सरकार ने महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉफ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा- महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। इनमें 25 की शिनाख्त हो चुकी है।

घटना के 17 घंटे बाद सरकार ने की 30 मौतों की पुष्टि, 25 डेड बॉडी की हुई शिनाख्त

भगदड़ उस वक्त मची, जब लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या स्नान के लिए कर रहे थे प्रतीक्षा

राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस बीच, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भगदड़ को विपक्ष की साजिश बताते हुए इसे जांच का विषय करार दिया

पलामू की एक महिला की भी मौत, बहन गंभीर

प्रयागराज महाकुंभ में पलामू जिले की एक महिला की भी मौत हो गई है। जबकि, गढ़वा जिले की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार पलामू जिले के रेहला थाने के तोलरा गांव की महिला गायत्री देवी(60) साल की भगदड़ में जान चली गई है। गायत्री देवी पति अमरेश पांडेय, गढ़वा जिले के झुरा निवासी बहनोई कयास दुबे व बहन तेतरी देवी व अन्य रिश्तेदारों के साथ कुंभ स्थान को गई थी। अमरेश पांडेय का एक बेटा सीआरपीएफ में हैं। उसकी ड्यूटी कुंभ मेला में लगी हुई है। बेटे ने मां-बाप व अन्य रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी एक साथ प्रयागराज गए थे। अमरेश पांडेय ने बताया कि हमलोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने की लिए रात में ही संगम तट पर पहुंच गए थे।

> महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकसंतप्त तीर्थयात्री परिवारों के साथ हैं। इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
>
> **हेमंत सोरेन, सीएम।**

SHARE

सेंसेक्स	:	76,532.96
निफ्टी	:	23,163.10

SARAFA

सोना	:	7,770
चांदी	:	104.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

ईडी ने पूजा सिंघल पर केस चलाने के लिए मांगी अनुमति

RANCHI : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर केस चलाने की अनुमति मांगी है। बता दें कि बीएनएसएस 2023 की धारा 218 में उल्लिखित है किसी लोकसेवक के खिलाफ केस चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि बीते 21 जनवरी को झारखंड सरकार ने भी पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त कर दिया था। इससे पहले उन्हें 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया था। 7 दिसंबर 2024 को ही पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल को ईडी ने पीएमएलए 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया था।

स्टेट कैबिनेट : छह प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने वाले होंगे पुरस्कृत

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को पुरस्कार देने की योजना पर मुहर लगाई गई। अन्य 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने दी। बताया कि झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवॉर्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कुल नौ पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया जाएगा।

शिक्षा और साक्षरता विभाग नौ पुरस्कारों से करेगा सम्मानित

- हर वर्ष कम से कम तीन शिक्षकों-छात्रों व संस्थानों का किया जाएगा चयन
- सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी स्मारिका
- शोध के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने किया फैसला

इन प्रस्तावों को भी दी गई स्वीकृति

कैबिनेट ने हाईकोर्ट के न्यायादेश पर सेवानिवृत्त राजकुमार राम की सेवा संपुष्ट करते हुए अनुमानन्य वित्तीय लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है। इसी तरह विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में विजय कुमार ठाकुर सेवानिवृत 30 अप्रैल 2024 को वरीय अनुदेशक रूप से नियुक्त करते हुए पेंशन आदि लाभों की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दर में वृद्धि 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो बर्खास्त

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रांची में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। मतियस विजय टोप्पो वर्तमान में हजारीबाग के निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण अभिकरण के पद पर हैं। इन पर धारा 71 ए के तहत पद का दुरुपयोग कर ऐसे मामले जिसमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हुए थे, उसका बिना किसी समुचित जांच के आदिवासी जमीन की क्षतिपूर्ति के आधार पर भूमि के अवैध हस्तांतरण का आरोप है।

मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को किया ढेर, एक जवान घायल

PHOTON NEWS CHAIBASA : बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर कर दिए गए। घटनास्थल से दो इंसास राइफल भी बरामद किए गए हैं। इसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे दायीं हथेली में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलाइती टोला के पास जंगल में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवानों की टीम संयुक्त रूप से जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी दौरान उनका नक्सलियों के साथ आमना-सामना हो गया। पुलिस को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली भागने लगे। सर्च अभियान के दौरान अभी तक दो नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में हुआ एनकाउंटर, दो इंसास राइफल जब्त

- मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल
- झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर के जवानों की टीम चला रही थी सर्च ऑपरेशन
- टीम को देखते ही नक्सलियों ने शुरू कर दी फायरिंग

अमित मुंडा गिरोह की मिली थी सूचना

घटना की पुष्टि करते हुए एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि वे घटनास्थल पर स्वयं मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को गुप्त सूचना मिली थी कि 15 लाख का इनामी नक्सली अमित मुंडा सोनुआ इलाके में अपने दस्ते के साथ विध्वंसक कार्रवाई के लिए सक्रिय है। इस सूचना पर सुरक्षाबल के जवान सोनुआ थाना क्षेत्र के लोंजो नाचल्दा के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने दोनों साथी का शव छोड़कर भाग निकले। खबर यह भी है की इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है।

न्यू रिसर्च वैश्विक रिपोर्ट में साइंटिफिक टेंपर की दी गई है विस्तृत जानकारी

धर्म के साथ विज्ञान में भी यकीन रखते हैं भारत के लोग

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : भारत, मिस्र और यूनान दुनिया के प्राचीनतम देशों में शामिल हैं। भारत एशिया में मिस्र उत्तर पूर्व अफ्रीका में और यूनान यूरोप महादेश में है। ये तीनों देशों अपनी सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता के लिए जाने जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी इन तीनों देशों का योगदान अमूल्य है। धर्म की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। धर्म के साथ विज्ञान के प्रति यहां के लोगों का प्राचीन काल से ही अटूट विश्वास करता है। अभी हाल में हुए स्पेशल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि दुनिया में विज्ञान में विश्वास करने वाले देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। धर्म के प्रति यहां के लोगों की तो अटूट आस्था है। यह सही है कि भारत के लोग विज्ञान पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि विज्ञान के प्रति जनता का भरोसा भारत में मिस्र के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर बात पूरी दुनिया की जाए तो यह मध्यम स्तर पर है। वैश्विक दक्षिण के कम शोध वाले देशों समेत 68 मुल्कों के लोगों को विज्ञान पर इस सर्वे में शामिल किया गया, जिन्होंने इस विषय में अपनी राय का इजहार किया है।

अधिकतर लोगों की चाहत है कि वे वैज्ञानिक समाज और राजनीति में निभाएं भूमिका

पूरी दुनिया में मिस्र के बाद दूसरे स्थान पर भारतीयों की वैज्ञानिक बुद्धि

समाज में लोगों की सोच पर विचारधारा का भी पड़ता है प्रभाव

- विज्ञान और वैज्ञानिकों में विश्वास के संकट का कोई सबूत नहीं
- ऑस्ट्रेलिया पांचवें न्यूजीलैंड नौवें और अमेरिका 12वें पायदान पर
- व्यापक सर्वे में 68 देशों के 72 हजार लोगों की राय की गई है शामिल
- नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक जर्नल में प्रकाशित की गई है रिपोर्ट

आम लोगों से वैज्ञानिक संवाद की जरूरत

सर्वे में एक महत्वपूर्ण बात पता चली है। खासतौर से पश्चिमी देशों में दक्षिणपंथी राजनीतिक विचार वाले लोगों का विज्ञान पर उतना भरोसा नहीं है, जितना वाम विचार वाले लोग इस पर विश्वास करते हैं। सर्वे में शामिल 83 फीसद लोग मानते हैं कि वैज्ञानिकों को विज्ञान के बारे में आम लोगों से संवाद करना चाहिए। 52 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वैज्ञानिकों को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। सर्वे के रिजल्ट बताते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिकों में विश्वास के संकट वाले दावे का कोई सबूत नहीं मिला है। विक्टोरिया के अनुसार, सर्वे के नतीजों से पता चलता है कि ज्यादातर देशों में अधिकतर लोगों का वैज्ञानिकों पर अपेक्षाकृत उच्च स्तर का भरोसा है।

कोरोना के बाद किया गया सर्वे

स्विट्जरलैंड की प्रमुख शोधकर्ता विक्टोरिया कोलोग्ना ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद पहली बार हुए इस सर्वे में करीब 72 हजार लोग शामिल हुए। नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक जर्नल में प्रकाशित में रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति जनता के भरोसे के मामले ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड नौवें और अमेरिका 12वें पायदान पर है। लोग चाहते हैं कि वैज्ञानिक समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। इतना ही नहीं, सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकतर लोगों ने वैज्ञानिकों को योग्य (78%), ईमानदार (57%) और जनता की भलाई के प्रति चिंतित (56%) माना है।

जीएसएलवी-एफ15 को इसरो ने सफलतापूर्वक किया लॉन्च

SRIHARIKOTA : बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण सफल रहा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर एनवीएस-02 को ले जाने वाले जीएसएलवी-एफ15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने इस कामयाबी को लेकर कहा कि भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एनवीएस-02 उपग्रह को इसरो वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसका वजन 2250 किलोग्राम है। यह नई पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों में से दूसरा है। इसरो के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले वी. नारायणन के लिए यह पहला प्रक्षेपण है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्षेपण की निगरानी की।

सलीमा और निक्की को मिला भूखंड का पेपर

बेटियों ने अपनी प्रतिभा का मनवाया लोहा : हेमंत

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य की अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटन के कागजात सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को 3750-3750 वर्ग फीट के दो भूखंड प्रदान किए। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि इन खिलाड़ियों को अपना घर बनाने के लिए राज्य सरकार 35-35 लाख रुपये की मदद भी देगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वे न केवल राज्य, बल्कि देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं।

- राजधानी रांची की हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में दी गई है जमीन
- अपना घर बनाने के लिए दोनों को राज्य सरकार 35-35 लाख रुपये की देगी मदद

फोरलेन टोल प्लाजा के पास फायरिंग करने वाले शूटर किए गए गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में तीनों आरोपी • फोटोन न्यूज

एनएच-39 स्थित चुकरू में 7 जनवरी को अपराधियों ने चलाई थी गोली

AGENCY PALAMU : पुलिस ने एनएच 39 फोरलेन सड़क निर्माण के क्रम में सदर थाना क्षेत्र के चुकरू स्थित टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और गोली बरामद की गयी है। इस घटना को अंजाम दिलाने वाले राहुल सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की गयी है। बताते चलें कि 7 जनवरी को गोली चली थी। एक मजदूर के पैर में गोली लगी थी। इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में मुख्य शूटर शुभम दुबे को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर दूसरा शूटर आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका के रहने वाले हैं।

मामले की जानकारी देतीं एसपी रीष्मा रमेशन • फोटोन न्यूज

जिले की एसपी रीष्मा रमेशन ने बुधवार को बताया कि रंगदारी के लिए लातेहार के अपराधी राहुल सिंह के नाम पर गोली चलायी गयी थी। इस घटना के बाद अमन साव गिरोह से जुड़े मयंक सिंह ने क्रेडिट लेते हुए जिम्मेवारी ली थी। साथ ही कंपनी के कर्मियों को रंगदारी के लिए धमकाया था। दरअसल एनएच फोरलेन निर्माण करा रही भारत वाणिज्य इस्ट प्राइवेट लिमिटेड से राहुल सिंह, अमन साव और रांची के कृष्णा यादव ने रंगदारी मांगी थी। अनुसंधान के क्रम में मंगलवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोली चलाने वाला युवक शुभम दुबे रेड़मा की तरफ घूम रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मणिभूषण प्रसाद, सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, रंजीत कुमार, मनोज मुंडा एवं जवानों ने कार्रवाई कर शुभम को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक पिस्टल, तीन जिंदा गोली, एक खाली मैग्जिन एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गयी। एसपी ने बताया कि शुभम की जानकारी पर आकाश को पकड़ा गया। घटना में आकाश की मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। नंबर प्लेट बदल कर इस्तेमाल में लायी गयी थी। हथियार शुभम के बेलवाटिका स्थित पुस्तैनी घर से बरामद किया गया।

भारी मात्रा में 43 लाख का नकली शराब बरामद, एक हुआ गिरफ्तार

बरामद शराब व आरोपी के साथ मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

HAZARIBAG : जिला के कटकमदाग थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात भारी मात्रा में शराब बरामद की है। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन मामले की जानकारी दी। पंकज ने बताया कि हुरूदाग गांव में एक व्यक्ति के जरिये नकली शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के जरिये टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इसी दौरान एक व्यक्ति को भी पुलिस पकड़ने में सफलता पाई और दो फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम क्रिस्टोपाल हंस (22) बताया गया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाईल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि शराब करीब 43 लाख रुपये का बरामद हुआ है। इसके अलावा कांच का खाली बोतल जिसमे भी बरामद की गई है।

पलामू में गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

PALAMU : मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाये जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उतरप्रदेश के वाराणसी में गांजा तस्करी की योजना को विफल करते हुए करीब नौ किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी डालटनगंज रेलवे स्टेशन से वाराणसी जाने की तैयारी में थे। उनके पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किये गये हैं। तस्करों की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के डंडारकला के हबीस अंसारी (19), पकरिया के दिलीप कुमार (20) और पिंटू कुमार (21) के रूप में हुई है। शहर थाना में मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति रेलवे स्टेशन के सामने नवनिर्मित भवन के पास अवैध गांजा की खरीद बिक्री करने आ रहे हैं। सूचना के बाद सदर सीओ अमरदीप सिंह बल्होत्रा, शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार, गुलशन बिरवा, संदीप कुमार भारती, अभिमन्यू कुमार के अलावा जवानों के जरिये कार्रवाई की गयी।

BRIEF NEWS

पश्चिमी सिंहभूम ने गुमला को हराया

CHAIBASA : झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे अंतर जिला अंडर-19 (एलिट ग्रुप) क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को खेले गए ग्रुप-बी के लीग मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने गुमला को एकतरफा मुकाबले में 206 रनों के भारी अंतर से पराजित कर पूरे चार अंक हासिल किए। पश्चिमी सिंहभूम की ये लगातार दूसरी जीत है। आज की जीत के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के कुल 8 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में ये पहले स्थान पर पहुंच गई है। रांची के उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेले गए इस मैच का टॉस पश्चिमी सिंहभूम के कप्तान ने जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पश्चिमी सिंहभूम के बल्लेबाजों ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए। जीत का पीछा करने उतरी गुमला की पूरी टीम 39.2 ओवर में मात्र 114 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के बल्लेबाज डेविड सागर मुंडा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मुंडा को मंगलवार को भी धनबाद के विरुद्ध 91 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था।

ब्लैक स्पॉट पर बालू के बोरे रखने का निर्देश

RAMGARH : चुट्टूपालू घाटी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के आलोक में बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मनीषा वत्स ने घाटी और पुंदाग टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। चुट्टूपालू घाटी के निरीक्षण के क्रम में डीटीओ ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित गंडके मोड पर ब्रेक फेल होने की स्थिति में सुरक्षा दृष्टिकोण से बालू के बैग्स रखने का निर्देश दिया। टोल और एनएचएआई के पदाधिकारियों को पर्याप्त संख्या में घाटी में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों से संबंधित साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने चुट्टूपालू घाटी में सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, स्पीड गति बोर्ड, लाइट आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान डीटीओ ने एनएचआई के संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द बचे हुए कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुनदाग टोल प्लाजा पर भारी वाहन चालकों को घाटी में प्रवेश करने के पूर्व एवं घाटी में वाहन संचालन करने के दौरान ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने सभी चालकों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, वाहन के फिटनेस पर विशेष ध्यान देने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जागरूक किया।

आचार संहिता मामले में श्रम मंत्री की न्यायालय में पेशी

व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए जाते मंत्री संजय यादव • फोटोन न्यूज

DUMKA : व्यवहार न्यायालय के एमपी -एमएलए सह एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय मे झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री संजय यादव पेश हुए। कोर्ट मे पेश होने के बाद मंत्री संजय यादव बुधवार को रांची मे होने वाले कैबिनेट की बैठक मे शामिल होने के लिए रवाना हो गये। गोड्डा जिला के पथरगामा थाना मे 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव अचार संहिता उल्लंघन मामले मे मंत्री संजय यादव पर मामला दर्ज हुआ था। मामले में गवाहों की गवाही शुरू है।

वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक होने के कारण कोर्ट के आदेश पर श्रम मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए रांची के लिए प्रस्थान कर गए।

सड़क सुरक्षा के लिए डीसी ने लगाई दौड़

जिला खेल स्टेडियम में हुआ समापन समारोह, नुक्कड़ नाटक से भी दिया गया संदेश

AGENCY LATEHAR : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को समाहरणालय परिसर से मैराथन दौड़ शुरू हुआ, जिसे उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका समापन कारगिल चौक होते हुए जिला खेल स्टेडियम में किया गया। इसमें नारे लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। दौड़ में जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्टूडेंट्स, खिलाड़ी आदि शामिल थे। समापन पर गुड समरिटान पॉलिसी के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले मनिका प्रखंड के अख्तर अंसारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीरता

दौड़ लगाते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता व अन्य पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

से पालन करें और यातायात के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनें। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।

उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नलों के पालन पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के बारे में जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक की टीम के सदस्यों ने लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, अत्यधिक रफ्तार से गाड़ी नहीं चलने व जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी धीरे करने की जानकारी दी।

वहीं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डेन ऑवर (एक घंटे के अंदर) हॉस्पिटल लेकर जाने पर सरकार द्वारा संचालित गुड समरिटान योजना अंतर्गत सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रुप में 5000 रुपये देने के प्रावधान के बारे में बताया।

रोजगार सृजन योजना के लाभुकों के दस्तावेजों की हो ठीक से जांच : डीसी

AGENCY RAMGARH : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उचित लाभुकों को ही मिलना चाहिए। जितने भी लोगों ने आवेदन दिया है उनके दस्तावेज की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। यह निर्देश बुधवार को डीसी चंदन कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान दिया। जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जानकारी दी। अब तक दिए गए लाभुकों के लाभ के संबंध में भी जानकारी दी। उपायुक्त ने प्राप्त आवेदनों का दस्तावेज को अच्छे से जांच के बाद ही योग्य लाभुकों को लाभ देने का निर्देश दिया। बैठक के

बैठक करते उपायुक्त चंदन कुमार • फोटोन न्यूज

दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिन लाभुकों का राशि स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें अभिलंब लाभ दें।

जो लाभुक स्वीकृति के बाद भी लाभ नहीं ले रहे हैं उन सभी को नोटिस करें। लाभुक स्वीकृत राशि योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो संबंधित राशि को अन्य लाभुकों में स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने अब तक जितने भी लाभुक लाभ ले चुके हैं, उन सभी की जानकारी ली। उन्होंने दिए गए रोजगार के लिए लाभ का सही उपयोग करने को कहा। इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश डीसी ने दिया है। बैठक में डीडीसी रोबिन टोप्पो, डीटीओ मनीषा वत्स, एलडीएम दिलीप महली सहित अन्य उपस्थित थे।

हजारीबाग में ट्रेन से कटकर एक की मौत

HAZARIBAG : हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन के ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव कटकमदाग पुलिस ने बरामद किया है। घटना बुधवार दोपहर बाद की है। कटकमदाग थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के सिरसी के पास रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। शव की पहचान के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।

नकली नोट बनाने के आरोप में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

GODDA : पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को गुप्त सूचना मिली थी कि महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊर्जानगर के हेलीपैड के आसपास 3-4 व्यक्ति रुपये (नोट) बनाने के नाम पर लोगों को ठगने के उदेश्य से एकत्र हैं।

इस सूचना पर महगामा के पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची। रात करीब 8.40 बजे वहां घेराबंदी कर एक स्कॉर्पियो में सवार 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें रखे एक बैग से ठगी करने के उद्देश्य से बनाए गए कागज के रुपये जैसा बंडल व केमिकल बरामद हुआ। गिरफ्तार होने वालों में बांका (बिहार) निवासी संजय कुमार, मो. नैयर व मो. इकबाल आलम शामिल हैं।

सोनुवा में नक्सलियों को मारने वाले पुलिस जवानों को किया गया सम्मानित

नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो बुरी मौत मारे जाएंगे : डीजीपी

CHAKRADHARPUR : डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे सरेंडर करें, , नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। सोनुआ में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी के बाद डीजीपी उत्साहित दिखे।

वे रांची से चक्रधरपुर पहुंचे। यहां सीआरपीएफ के कार्यालय में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों को पुरस्कृत व सम्मानित किया। डीजीपी ने खुशी जाहिर करते हुए पत्रकारों से कहा कि इनका मारा जाना बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है। कितने लोग इनकी हिंसा से परेशान हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि मौजूदा दौर में अब इन्हें नक्सली भी कहना सही नहीं है। डीजीपी ने नक्सलियों

पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीजीपी अनुराग गुप्ता • फोटोन न्यूज

को गुंडा कहा। उन्होंने कहा कि नक्सली अब गुंडे बनकर लूटपाट और हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पहले यह नक्सली गरीबी और मजबूरी के साथ साथ सरकारी व्यवस्था से नाराज होकर हथियार थामकर नक्सलवाद के रास्ते को अख्तियार करने की बात करते थे। लेकिन आज बहुत कुछ बदल चुका है। गांव में बिजली, पानी, सड़क सब कुछ पहुंच चुका है। गांव का विकास तेजी से हो रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की योजनाएं गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत कर रही हैं। मंईयां सम्मान योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर घर की महिला के हाथ में आज पैसा जा रहा है, तो फिर ये कौन लोग हैं, जो नक्सलवाद का चोला ओढ़कर समाज में गंध मचा रहे हैं। बोकारो और चतरा के ये मारे गए नक्सली पश्चिम सिंहभूम की शांति को भंग कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से जो सामान बरामद हुए हैं, उससे नक्सलियों के कई बड़े भेद खुल चुके हैं। नक्सलियों का बड़ा डाटा उनके हाथ लग चुका है। अब कोई नक्सली बच नहीं पाएगा। डीजीपी ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि इस मुठभेड़ में उनका एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान का एक अंगूठा हमेशा के लिए खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि घायल जवान का बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाएगा, ताकि उसका हाथ ठीक हो जाए। चक्रधरपुर स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में डीजीपी ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को सम्मानित करने के बाद उनका हौसला बढाया और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में जो अधिकारी मौजूद थे, उनमें जिले के एसपी आशुतोष शेखर, डीसी कुलदीप चौधरी, अभियान एसपी पारस राणा, सीआरपीएफ 60 बटालियन कमांडेंट, अंबुज मुथाल, रांची अभियान एसपी नाथु सिंह मीणा, आईजी अखिलेश झा, आईजी साकेत कुमार, कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे, एसडीओ श्रुति राज लक्ष्मी, डीडीसी संदीप मीणा, सीआरपीएफ डीआईजी सहित सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल के अधिकारी और जवान।

उपायुक्त ने कम मानव दिवस सृजन वाले प्रखंड के पदाधिकारियों को उपलब्धि बढ़ाने के दिए निर्देश

AGENCY LOHARDAGA : उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विकास समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश पदाधिकारियों को दिये गये। मनरेगा अंतर्गत 2024-25 में प्रखण्डवार मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। कम मानव दिवस सृजन वाले प्रखण्ड के पदाधिकारियों को उपलब्धि बढ़ाने के निर्देश दिये गये। बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना अंतर्गत सभी प्रखण्डों को अपनी उपलब्धि सौ फीसदी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मनरेगा के विभिन्न योजनाओं, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन अंतर्गत तैयार किये गये पशु शेड, दीदी बाड़ी योजना, एरिया अफसर एप में एंट्री

बैठक करते उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण • फोटोन न्यूज

की समीक्षा की गई। अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में लंबित आवेदनों को स्वीकृत का योजना का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को आवेदकों के वेटिंग लिस्ट आवास योजना के लिए लंबित आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। पीवीटीजी के संचालित पीएम जनमन योजना में लंबित लक्ष्य को जल्द आच्छादित किये जाने का निर्देश दिया गया। जिन आवेदकों का आधार अपडेट नहीं है उनके आधार अपडेशन के लिए परियोजना पदाधिकारी, यूआइडी को संबंधित पंचायतों में कैंप लगाकर आधार अपडेशन का कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। नीति आयोग के अवार्ड मनी से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मिलेट, पल्स प्रोडक्शन यूनिट, दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रोडक्शन यूनिट, बीएस कॉलेज में लाईब्रेरी अधिष्ठान, सदर प्रखण्ड में दीदी कैफे का निर्माण आदि योजनाएं शामिल हैं।

Weather
28.0° Highest Temperature
14.0° Minimum Temperature
Sunrise Tomorrow 06.30
Sunset Today 17.35
CITY
03
Daily THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
www.thephotonnews.com
Thursday, 30 January 2025

BRIEF NEWS

झारखंड का नया सचिवालय जल्द बनकर होगा तैयार

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार का नया सचिवालय बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यह सचिवालय धुर्वा के कुटे में नए विधानसभा भवन के पास 35 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। विभाग नए सचिवालय का डिजाइन तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है।

केबल ब्रिज का काम पूरा सिर्फ 6 मीटर जोड़ना बाकी

RANCHI : सिरमटोली फ्लाईओवर का रेलवे एरिया में काम लगभग पूरा हो गया है। राजेंद्र चौक डोरंडा और पटेल चौक की ओर से केबल स्टे ब्रिज झुलाने का काम पूरा कर दिया गया है अब बस दोनों ओर से इसे जोड़ने का काम बाकी है। करीब छह मीटर इसे जोड़ा जायेगा जिससे पटेल चौक और राजेंद्र चौक तक ब्रिज आपस में जुड़ जाएगा। इंजीनियरों ने बताया कि रेलवे की ओर से अगला ब्लॉक मिलते ही यह काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद आसानी से मेकॉन की ओर से पटेल चौक तक आना-जाना हो सकेगा। इंजीनियरों का कहना है कि यह प्रयास हो रहा है कि मार्च तक इस योजना को पूरा करा दिया जाए।

आरईओ में 30 जूनियर इंजीनियरों की हुई पोस्टिंग

RANCHI : ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) में 30 जूनियर इंजीनियरों का पदस्थापन कर दिया गया है। इन जूनियर इंजीनियरों की सेवा जल संसाधान विभाग से ली गई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जिन जूनियर इंजीनियरों का पदस्थापन आरइओ में किया गया है। उनमें मनन कुमार को विशेष प्रमंडल देवघर, उमेश कुमार को गुमला, अमित कुमार को सरायकेला, शशिकांत उरांव को रामगढ़,अभय रंजन को लोहरदगा, दुर्गा प्रसाद महतो को रामगढ़, विक्रम को गोड्डा, कृष्णकांत कुमार को चाईबासा, विकास आदित्य को गोड्डा, प्रवीण कुमार को पलामू, अजय कुमार को गुमला, मिहिर कुमार को गोड्डा, धीरेंद्र कुमार को जमशेदपुर, राजेश भगत को रांची,मृत्युंजय महतो को गुमला, चंद्रप्रकाश को साहेबगंज, शैलेश रंजन को साहेबगंज, दावानल प्रसाद मुर्मू को जमशेदपुर, विजय कुमार सिंह को सिमडेगा, हेमंत भगत को रांची, आलोक कुमार को लोहरदगा, शकील अंसारी को दुमका, अभय कुमार को जमशेदपुर, सुनील कुमार को सरायकेला, नरेश मंडल को लातेहार, सुमित कुमार को चाईबासा, जीतेंद्र पांडेय को बोकारो और मानिकचंद मुर्मू को गिरिडीह में पदस्थापित किया गया है।

सीनियर एडवोकेट की रेस में राज्य के 80 वकील

RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट में वरीय अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। राज्य के अलग अलग जिलों में प्रैक्टिस कर रहे 80 वकीलों ने वरीय अधिवक्ता के रूप में चयन के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इन वकीलों में झारखंड हाईकोर्ट, रांची सिविल कोर्ट, धनबाद सिविल कोर्ट समेत अन्य जिला न्यायालय के वकीलों का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 10-15 वकीलों का चयन ही वरीय अधिवक्ता के रूप में होना है। वर्ष 2017 के बाद से अब जल्द ही फुल कोर्ट की बैठक हो सकती है और वरीय अधिवक्ताओं का चयन किया जा सकता है। नियम के मुताबिक डेजिग्नेटिड सीनियर के रूप में चयनित होने के लिए वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस, अपने जूनियर वकीलों की जानकारी और महत्वपूर्ण मुकदमों में उनके द्वारा की गई पैरवी के अलावा कई बिन्दुओ पर जानकारी साझा कर दी है। फार्म भरने वाले वकीलों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जिला बार एसोसिएशन या स्टेट बार काउंसिल के में उक्त अधिवक्ता के खिलाफ मिसकंडक्ट या फिर प्रोफेशनल कंडक्ट का कोई आरोप तो नहीं है।

आचार संहिता उल्लंघन प्रथम दृष्टया सही, एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांस्फर हो सकता है केस

जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

PHOTON NEWS RANCHI : जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार रही महुआ माजी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में रांची पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 122/2024 में महुआ माजी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर अग्रिम सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार महुआ माजी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया है थाना क्षेत्र के कई सार्वजनिक स्थानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित प्रचार सामग्री लगाई गई थी।

रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज की गई थी एफआईआर

बीजेपी विधायक सीपी सिंह के खिलाफ भी आचार संहिता का केस पाया गया सही, चार्जशीट दाखिल

पूर्व मंत्री और भाजपा के रांची विधायक सीपी सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में रांची पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने रांची के हिन्दपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 123/2024 में सीपी सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर केस को अग्रिम सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान रांची विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सीपी सिंह के खिलाफ सहायक निवार्ची पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा गया है कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप का झंडा बंधा हुआ मिला था।

जेल में अमन सिंह की हत्या करने के आरोपी सतीश की बेल पर 30 को आएगा फैसला

गैंगस्टर अमन सिंह की जेल में हत्या करने के आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश गांधी की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सीआईडी की विशेष अदालत में सीआईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 30 जनवरी को सुनायेगी। बता दें कि धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर 2023 को गोली मारकर कर दी गयी थी। इस घटना की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी अब तक इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस केस के कुछ अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है।

गैंगस्टर अमन

कैपिटल विवि कोडरमा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर रोक

सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के बाद बुधवार को अब कोडरमा स्थित कैपिटल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कैपिटल यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले वर्ष राज्य सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया है। इसी एक्ट के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीसी एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया जाना है। लेकिन कोडरमा स्थित कैपिटल यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट के मुताबिक वीसी एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की है और सरकार के द्वारा लागू प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में हुई। कैपिटल यूनिवर्सिटी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने बहस की।

यौन शोषण मामले में चर्चा में आए पीएस नटराजन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, अब 8 मार्च को बहस

सुषमा बड़ाइक यौन शोषण मामले में चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी रहे पीएस नटराजन के मामले कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में सुनवाई जारी रही, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 8 मार्च की तिथि निर्धारित की। दरअसल, आईपीएस अधिकारी रहे पीएस नटराजन को बाद में कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट के द्वारा बरी किये जाने से पहले वर्ष 2012 में पीएस नटराजन को सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलकर बर्खास्त कर दिया गया था। जिसे पीएस नटराजन ने कैट में चुनौती दी थी। कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभागीय कार्रवाई जिसके माध्यम से उन्हें बर्खास्त किया गया था, उसे निरस्त कर दिया था। कैट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

झारखंड रेरा में अध्यक्ष व एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पद रिक्त रहने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बुधवार को झारखंड रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में अध्यक्ष एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रिक्त पद को भरने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड रेरा में वर्तमान में किसी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर रखकर काम चलाया जा रहा है,

● झारखंड रेरा राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को करता है नियंत्रित

झारखंड रेरा में 6 जनवरी 2021 से यह पद खाली पड़ा है। वही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है, जिससे 66 केस लंबित पड़े हैं। इन पदों को शीघ्र भरा जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ट्विंकल रानी ने पैरवी की। यहां बता दे कि झारखंड रेरा एक सरकार द्वारा स्थापित निकाय है जो राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर 10 को 'सुप्रीम' सुनवाई

राज्य सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हुई थी। इस दिन दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दरअसल इरफान अंसारी ने झारखड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमे हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के विरुद्ध चार्जफ्रेम किया था।

● बच्ची की फोटो वायरल होने के मामले में इरफान के खिलाफ अदालत ने लिया था संज्ञान

आर्यभट्ट सभागार में आयोजित त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल हुए गवर्नर

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति, न्याय और जनकल्याण की अप्रतिम प्रतीक : राज्यपाल

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति, न्याय और जनकल्याण की अप्रतिम प्रतीक बताते हुए कहा कि वे केवल एक कुशल प्रशासिका ही नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार की प्रतिमूर्ति थीं। उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किए। उनकी शासन-व्यवस्था पूरी तरह प्रजा के हितों पर केंद्रित थी। उन्होंने समाज को नई दिशा प्रदान की। वे राष्ट्र सेविका समिति (रांची महानगर) एवं रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, तब अहिल्याबाई जैसी महान विभूतियों के योगदान से हमें नई प्रेरणा मिलती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन न केवल प्रशासनिक दक्षता, बल्कि परोपकार और नारी सशक्तीकरण का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने इस समारोह के आयोजन के लिए राष्ट्र सेविका समिति एवं रांची विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए विश्वास प्रकट किया कि यह प्रयास लोकमाता अहिल्याबाई की प्रेरणादायी गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का कल्याण मंत्री ने किया उद्घाटन

स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को युवाओं तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य : चमरा लिंडा

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने डॉ.राम दयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड की जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। यह आयोजन झारखंड और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस चार दिवसीय शिविर का आयोजन धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया है, जिसमें राज्यभर के वरिष्ठ एवं युवा जनजातीय चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। इन चित्रों के माध्यम से वीर स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत और नीलांबर-पीतांबर के संघर्ष और योगदान को जीवंत किया जाएगा।

टाटीसिलवे में 14 फरवरी को कलश यात्रा में शामिल होंगी 2100 महिलाएं

ईईएफ मैदान में 15 से 22 तक चलेगी श्रीमद्भागवत कथा

PHOTON NEWS RANCHI : टाटीसिलवे के ईईएफ मैदान में 15 से 22 फरवरी तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाना है। प्रख्यात कथा वाचक इंद्रेश जी उपाध्याय 8 दिन तक भागवत प्रेमियों को कथा का रसपान कराएंगे। भागवत के सभी प्रसंगों का उल्लेख कर श्रद्धालुओं का आनंदित करेंगे। बुधवार को श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के कार्यालय में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई। श्रीमद्भागवत कथा अआयोजन समिति के अध्यक्ष रासेश्वर मिश्रा ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों में शिक्षा संस्कार सांस्कृतिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण संवर्धन और धार्मिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से 8 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन ईईएफ मैदान में किया जा रहा है। कथा आरंभ के एक दिन पूर्व 14 फरवरी को भव्य एवं विशाल कलशयात्रा निकाली जाएगा। इसमें 2100 महिलाएं शामिल होंगी। कलश यात्रियों को कलश, नारियल, पानी का बोतल एवं फलाहार समिति द्वारा दिया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक चलेगी। कलशयात्रा कथा स्थल ईईएफ मैदान से निकलकर स्वर्णरेखा तट तक पहुंचेगी।

साल 2023-24 में 36 लाख स्टूडेंट्स को मिली प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर फोकस कर रही सरकार

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 36 लाख विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृति प्रदान की। इस पर सरकार ने 1415 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की। चालू वित्तीय वर्ष 2025-25 में 21.54 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे चुकी है। इस पर 442 करोड़ रुपये निर्गत किए जा चुके हैं। सरकार अब तक 4.71 लाख विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरण कर चुकी है। साइकिल का वितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच किया गया। इस योजना के तहत वर्ग आठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल दी जा रही है। राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए 438 करोड़ का ऋण वितरित कर चुकी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7625 आवेदन स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लगभग 4 लाख 84 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 2 लाख 14 हजार प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर प्राप्त हुए। मनरेगा के तहत 714 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। 2430 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया।

● 4 लाख 71 हजार विद्यार्थियों को दी जा चुकी है साइकिल
● रोजगार सृजन के लिए 438 करोड़ का दिया गया कर्ज

जेबीवीएनएल ने क्षेत्रीय कार्यालय से मदद लेने की कस्टमर्स से की अपील

बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी

PHOTON NEWS RANCHI : जेवीवीएनएल (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ओर से उपभोक्ताओं से प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने महिंद्रा टायर किया जा रहा है। जेबीवीएनएल ने सूचना जारी करते कहा है कि निगम द्वारा प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में अब तक इसे नहीं लगाया जा सका है, वे जेबीवीएनएल के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1912 से संपर्क करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली कनेक्शन के साथ नहीं जुड़ा है, उनका मोबाइल नंबर और वाट्सएप नंबर को अपडेट किया जा रहा है। मोबाइल नंबर और वाट्स एप नंबर को अपडेट कराने को भी जेबीवीएनएल के टोल फ्री नंबर या इसके रीजनल ऑफिस यूनिवर्सिटी का नाममें संपर्क किया जा सकता है। नंबर अपडेट होने के पश्चात उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल उनके वाट्स एप नंबर पर भेजे जाएंगे। वाट्स एप के जरिए भी बिजली बिल डाउनलोड किया जा सकता है।

टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर उठाया जा सकता है लाभ

इन नंबरों पर भी किया जा सकता है संपर्क

जेबीवीएनएल ने रांची शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग रिजनल ऑफिसों के नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं। कोकर के कार्यपालक अभियंता से 9431135615, न्यू कैपिटल के कार्यपालक अभियंता से 9431135620 से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह रांची पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता से 9431135664, रांची पूर्वी से 9431135614, रांची सेंट्रल से 9431135613 और डोरंडा से 9470126508 पर संपर्क किया जा सकता है।

मेडिका ने कबड्डी स्टार धारवी के सपनों को दी नई उड़ान

PHOTON NEWS RANCHI : भगवान महावीर मेडिका सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने 17 साल की कबड्डी खिलाड़ी धारवी को घुटने की गंभीर चोट से उबारने में अहम भूमिका निभाई। धनबाद की रहने वाली धारवी जो रेलवे के लिए खेलती हैं। 2023 में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और मेडियल मेनिस्कस में चोट के कारण मुश्किलों का सामना कर रही थीं। जून 2023 में मेडिका हॉस्पिटल में उनकी आर्थोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की गई, जिसके बाद उन्होंने शानदार रिकवरी की। सर्जरी के बाद डॉ. निर्मल कुमार और डॉ. श्याम देव कुमार के मार्गदर्शन में धारवी ने तीव्र फिजियोथेरेपी से अपनी ताकत, फुर्ती और आत्मविश्वास को वापस पाया। धारवी की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही इलाज और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। धारवी ने इस अवसर पर डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब वह भारत और पीकेएल के लिए खेलने का सपना पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मेडिका हॉस्पिटल की यह सफलता खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर की देखभाल और उम्मीद प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। मौकेड से डॉ निर्मल कुमार (सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक साइंस), डॉ. राकेश अग्रवाल (सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक साइंस), डॉ. श्याम देव कुमार (सीनियर एसोसिएट, फिजियोथेरेपी) और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विजय कुमार मिश्रा मौजूद थे।

संतोष हत्याकांड में मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 5 गिरफ्तार

मानगो की मन्नान गली में 19 जनवरी को ट्रांसपोर्टर को खदेड़ कर मारी थी गोली

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसएसपी किशोर कौशल • फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR: मानगो थाना की पुलिस ने 19 जनवरी को हुए संतोष सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घटना के मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है।

एसएसपी किशोर कौशल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले में मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित गिरफ्तार हुआ है। वह मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला है।

इसके अलावा, उलीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर शिव मंदिर लाइन का रहने वाला शुभम कुमार, सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छाया नगर का रहने वाला विमल गोप, मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला विवेक कुमार तिवारी और मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला अंकित शर्मा भी गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, एक 315 बोर का कारतूस और हत्या में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि रोहित दीक्षित के पिता डब्बू दीक्षित की साल 2014 में हत्या कर दी गई थी। रोहित दीक्षित ने अपने पिता का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।

रौनक ने की थी रोहित की आर्थिक मदद

इस मामले में रौनक सिंह ने रोहित दीक्षित को आर्थिक मदद की और रेकी करने में भी मदद की। रौनक सिंह के पिता की हत्या साल 2009 में हुई थी। पुलिस ने रौनक सिंह और निखिल सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किया जा चुके हैं और कुछ और लोग भी इस मामले में लिप्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

युवक से मारपीट करने के मामले का आरोपी पकड़ाया

JAMSHEDPUR : साकची थाना क्षेत्र के काशीडीह में 25 जनवरी को दो गुटों के बीच झगड़ा हो रहा था। काशीडीह निवासी सम्राट सिंह इस झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था। सम्राट सिंह के साथ मारपीट भी हुई थी। पिस्टल लहराया गया था। इस मामले में साकची थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एसएसपी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना का आरोपी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मेंद्र यादव साकची के काशीडीह लाइन नंबर-1 का रहने वाला है। उसके पास एक पिस्तौल और एक मिस्ड कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर धर्मेंद्र यादव को जेल भेज दिया है। बता दें कि सम्राट सिंह, भाजपा नेता अभय सिंह का भतीजा है।

मानगो की समस्या पर गंभीर हुए जदयू कार्यकर्ता

JAMSHEDPUR : मानगो नगर निगम समिति की बैठक बुधवार को संयोजक कुलविंदर सिंह पन्नू की अध्यक्षता में उलीडीह आदर्शनगर स्थित पन्नू के आवास पर हुई। इसमें जदयू के वरिष्ठ नेता सुबोध श्रीवास्तव भी थे। समिति के सदस्यों ने मानगो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। तय हुआ कि समिति व्यापक रूप से संपर्क-समस्या-समाधान अभियान प्रारंभ करेगी और सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रातः नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वहां की समस्याओं का अवलोकन किया जायगा। भ्रमण के दौरान नगर निगम क्षेत्र की आम जनता से मुलाकात कर उनसे सीधा संपर्क स्थापित कर उनके इलाके की समस्याओं को जाना जाएगा। कचरा उठाव, साफ-सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, बिजली व पेयजल की आपूर्ति सहित अन्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर समाधान के लिए नगर निगम की अधिकारियों को कहा जाएगा।

भाजपा ने मानगो नगर निगम को घेरा, होल्डिंग टैक्स पर बोला हल्ला

निगम कार्यालय के बाहर पत्रकारों को जानकारी देते जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा

JAMSHEDPUR : भाजपा, जमशेदपुर महानगर ने मानगो क्षेत्र की जर्जर नागरिक सुविधाओं और नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को मानगो नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने नगर निगम की लापरवाही और नागरिक सुविधाओं की बदहाली पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए अविलंब समाधान की मांग की। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानगो नगर निगम की संवेदनहीनता और उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया गया कि मानगो क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कचरे का अंबार गलियों, सड़कों और नालियों में जमा हो गया है, जिससे कई गंभीर संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आज स्थानीय नागरिकों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बेखबर हैं। पार्टी ने मांग की कि कचरा निष्पादन की स्थायी व्यवस्था की जाए और सफाई व्यवस्था को नियमित किया जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मानगो की चार लाख से अधिक आबादी पानी की भारी किल्लत झेल रही है।

समाचार सार

अरका जैन के छात्रों ने सीखे शोध प्रस्ताव के गुर

JAMSHEDPUR : अरका जैन विश्वविद्यालय ने सरकारी एजेंसियों में अनुदान के लिए अनुसंधान प्रस्ताव लिखने पर दो दिवसीय कार्यशाला कराई, जिसमें पूर्व यूजीसी अधिकारी डॉ. अनंत राम ने अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के गुर सिखाए। डॉ. अनंत राम ने फंडिंग एजेंसियों की पहचान, प्रस्ताव लेखन की रणनीति और परियोजना प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के तरीके बताए। कार्यशाला विशेष रूप से विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए आयोजित की गई थी, ताकि वे सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए बेहतरीन अनुसंधान प्रस्ताव तैयार कर सकें।

महाशिवरात्रि की जोर-शोर से तैयारी

GHATSILA : महाशिवरात्रि को लेकर मऊभंडार शिव मंदिर परिसर में जोर-शोर से तैयारी हो रही है। मंदिर समिति के महासचिव नवल सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर बीएन सिंहदेव, एनके राय, जयंत उपाध्याय, मुनीब शर्मा, सुरेश सिंह चौहान, प्रकाश जायसवाल आदि भी उपस्थित थे।

स्कूली छात्रों को सिखाया गया विहंगम योग

JAMSHEDPUR : विहंगम योग टाटा संत समाज ने बुधवार को सुंदरनगर के कदमडीह स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्कूल में मेडिटेशन शिविर लगाया। इसमें शिक्षकों व छात्रों को विहंगम योग का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ प्रचारक सह उपदेष्टा पं. योगेंद्रनाथ पांडेय व उपदेष्टा आशा पांडेय ने विहंगम योग से होने वाले लाभ पर प्रकाश डालते हुए सभी विद्यार्थियों को क्रियात्मक अभ्यास कराया। विद्यालय की लाइब्रेरी को स्वर्वेद पुस्तक भी भेंट की गई। इस मौके पर जिला संयोजक बिजेंदर उपाध्याय व समन्वयक नीरज मिश्रा भी उपस्थित थे।

सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट

JAMSHEDPUR : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला अस्पताल (सदर अस्पताल) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। सदर अस्पताल को 86% अंक प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष 2023 में भी सदर अस्पताल को यह सर्टिफिकेट मिला था। इस उपलब्धि पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल समेत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने से जिले के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों का उत्साह दोगुना हुआ है।

सेंट मेरीज के बच्चों ने पैरेंट्स नाइट में बांधा समां

JAMSHEDPUR : बिष्टुपुर स्थित सेंट मेरीज स्कूल में बुधवार को पैरेंट्स नाइट हुआ, जिसमें केजी के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति से समां बांध दिया। आवर वंडरलैंड यानी हमारा परीलोक नामक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि फादर आल्यीन वीकर, जनरल जमशेदपुर धर्मप्रांत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बच्चों के द्वारा ईश्वर की अनमोल कृति यानी हमारी सुंदर प्रकृति पर आधारित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पृथ्वी पर विनाश को रोकने का संदेश दिया।

एनएसयू की बस को ट्रक ने मारी टक्कर

JAMSHEDPUR : एमजीएम थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-33 पर बुधवार को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जा रही बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे तीन स्टूडेंट्स घायल हो गए। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया था। घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए टीएमएच भेजा गया। यहां स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा है। बताते हैं कि नेशनल हाईवे पर लिट्टी चौक के पास बस और ट्रक में टक्कर हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जमशेदपुर की समस्या को लेकर सीएम से मिले बन्ना

रांची में मुख्यमंत्री से बात करते बन्ना गुप्ता • फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, जिसमें उनसे जमशेदपुर से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की। बन्ना गुप्ता ने बताया कि पिछले कई दिनों से मानगो के कचरे का निष्पादन करने के लिए समस्या हो रही है। इसके साथ ही मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य में तेजी लाने का विशेष निर्देश अधिकारियों एवं संबंधित कंपनी को देने का आग्रह किया, आगामी गर्मी के मौसम में सुचारु विद्युत व्यवस्था व पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने का निर्देश भी अधिकारियों को देने का आग्रह किया। इसके साथ शहर में बेहतर लॉ एंड आर्डर समेत क्षेत्र के विभिन्न अन्य मुद्दों पर सकरात्मक बातचीत कर हल निकालने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया। बन्ना ने बताया कि सीएम ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द समाधान देने का आश्वासन दिया है।

एग्रिको में 3 से 7 तक लगेगा आधार शिविर

JAMSHEDPUR : एग्रिको स्थित विधायक के कैंप कार्यालय के समीप 3 से 7 फरवरी तक आधार शिविर लगेगा, जिसमें क्षेत्र के नागरिक नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे और पहले से बने कार्ड में जरूरी सुधार करवा सकेंगे। आधार कार्ड आज नागरिकों की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। लेकिन, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की इस परेशानी को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अधिकारियों से वार्ता कर इसके समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

ऊपरपावड़ा स्कूल से लापता छात्र का 9 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

परियोजना निदेशक ने प्रधानाध्यापक को किया शोकॉज

स्कूल परिसर में शिक्षकों से पूछताछ करतीं बीडीओ युनिका शर्मा (बाएं)

PHOTON NEWS GHATSILA : घाटशिला प्रखंड के ऊपरपावड़ा में संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय से 9 दिनों से लापता तीसरी कक्षा के छात्र सुशील मुर्मू का अभी तक पता नही चला है। इससे विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री के मंगलवार को विद्यालय का दौरा करने के बाद प्रशासन और कल्याण विभाग भी हरकत में आ गया है। यही कारण है कि बुधवार को बीडीओ युनिका शर्मा, एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर, थाना प्रभारी मधुसूदन दे, जिप सदस्य देवयानी मुर्मू आदि ने स्कूल जाकर लापता बच्चे के अन्य साथियों से घंटों पूछताछ की। प्रधानाध्यापक और बच्चों के अभिभावक से भी थाना बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जगह-जगह जाकर सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। दूसरी ओर कल्याण विभाग की ओर से परियोजना निदेशक ने स्कूल के प्रधानाध्यापक कालीचरण स्वांसी को बच्चे के गायब होने की जानकारी छिपाने और विभाग को किसी प्रकार की जानकारी से अवगत नही कराने का आरोप लगाते हुए शोकॉज किया है। बच्चे के नहीं मिलने पर कार्रवाई की लिए भी तैयार रहने को कहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य कालीचरण स्वांसी ने कहा कि बच्चे के गायब होने की खबर काफी देर बाद पता चली। बच्चे के खोजने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नही चला है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बोले जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक

एमजीएम की नई बिल्डिंग में भूमिगत जल का इस्तेमाल न हो : सरयू राय

विधायक सरयू राय

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि नए एमजीएम अस्पताल भवन में भूमिगत जल का उपयोग नहीं करें, डीप बोरिंग नहीं करें। डीप बोरिंग करने से आसपास के इलाकों में चापाकल सूख जाएंगे और आम जनता परेशान होगी। अस्पताल के संचालन के लिए जो पर्यावरण स्वीकृति ली गई है, उसमें भूमिगत जल के इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है। सरयू राय ने कहा कि प्रावधान के अनुसार, नगर निगम से इस बात की स्वीकृति लेनी है कि वह एमजीएम अस्पताल को प्रतिदिन 300 लाख लीटर पानी देगा। अस्पताल में कुल करीब 500 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी, उसमें से शेष जल को उपयोग में आने वाले जल को शुद्ध करके इस्तेमाल किया जाएगा। राय ने कहा कि बोरिंग करना तो पर्यावरण स्वीकृति के प्रावधान के भी विरोध में ही है। पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री ने इसकी व्यवस्था नहीं की। यह नहीं सोचा गया कि अस्पताल के परिचालन के लिए पानी कहां से आएगा। ऐन चुनाव के वक्त हड़बड़ी में एमजीएम की ओपीडी को एमजीएम के नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय तक उस भवन को भी ठेकेदार ने हैंडओवर नहीं किया था। आज तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अस्पताल संचालन के लिए सहमति नहीं मिली है। जब शीर्ष पर बैठे अधिकारी और मंत्री ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो आम जनता के लिए क्या ही कहा जा सकता है। राय ने प्रधान सचिव को दो विकल्प सुझाए। पहला-जमशेदपुर के लिए मानगो होकर डिमना लेक का पानी जाता है तो उसमें से ही टाटा स्टील अस्पताल को कनेक्शन दे दे। दूसरा-पारडीह के पास सतनाला डैम है। वहां प्रचुर पानी है। वह जैम ऊंचाई पर है।

टाटा स्टील, ट्यूब की डिस्पेंसरी खोलने की मांग

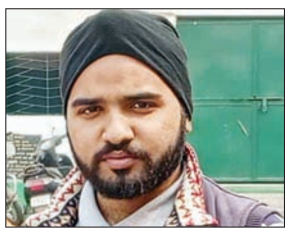

JAMSHEDPUR : टाटा स्टील द्वारा 2025 में कई नियम लागू किए हैं, जिसके तहत टाटा स्टील, ट्यूब डिवीजन बमामाईंस की डिस्पेंसरी को सोमवार से बंद कर दिया गया। इससे बुजुर्गों सहित सभी पेशेंट को काफी परेशानी हो रही है। समाजसेवी करनदीप सिंह ने टाटा स्टील और उपायुक्त को ट्वीट कर इस डिस्पेंसरी को खोलने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को एक पेशेंट डायलिसिस के लिए बारीडीह डिस्पेंसरी गया, उसे वहां कहा गया कि आप टीएमएच चले जाइए, वहां दवा मिल जाएगी।

सभी मुखिया ने की नल-जल योजना अधूरी रहने की शिकायत

सभी पंचायतों के मुखिया से बात करते विधायक जगत माझी • फोटोन न्यूज

SONUA : सोनुआ प्रखंड में नल-जल एवं जलमीनार योजना में अनियमितता बरती गई हैं। इसका खुलासा बुधवार को विधायक जगत माझी की उपस्थिति में हुई बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने की। सभी मुखिया ने बताया कि लगभग हर पंचायत में नल-जल योजना एवं जलमीनार से पेयजल आपूर्ति की शिकायत हैं। इस पर विधायक ने विभाग के सहायक अभियंता समीर डुंगडुंग को एक महीने में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। वहीं प्रखंड में नए पशु शेड के निर्माण एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की गति से भी विधायक असंतुष्ट नजर आए। विधायक ने अबुआ आवास एवं पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए चयन में योग्य लाभुक को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। बिजली विभाग की समीक्षा में पता चला कि सोनुआ के करीब 35 टोला में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। विधायक ने विभाग से कमियों को दूर कर बिजली पहुंचाने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में मुखियाओं ने शिकायत कि की छात्रा-छात्राओं में वितरित किए गए साइकिल में अधिकतर अनफिट थे।

पत्नी से मंगलवार रात 11 बजे हुई थी बात, कहा था-यहां काफी भीड़ है...

कुंभ की भगदड़ में मुसाबनी के एक व्यक्ति की मौत

मृतक की फाइल फोटो

PHOTON NEWS GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला एवं मुसाबनी से उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में डुबकी लगाने गए मुसाबनी निवासी शिवराज गुप्ता (58) की मंगलवार को कुंभ में मची भगदड़ के दौरान मौत हो गई, वहीं घाटशिला की दो महिला सुनैना देवी (50) व सरिता देवी (45) लापता हैं। दोनों महिला के लापता होने के बाद से उनके साथ गए परिजन खोज-खोज कर परेशान हैं। मेला में माइक से दोनों महिला का नाम भी पुकारा जा रहा है। इसके बावजूद महिला नहीं मिल रही है।

जानकारी के अनुसार, मुसाबनी स्थित सुंदरनगर के रहने वाले शिवराज गुप्ता की मेला में मंगलवार रात लगभग 1.30 बजे भगदड़ के दौरान दबने के बाद सांस रुकने से मौत हो गई। शिवराज गुप्ता को-ऑपरेटिव बैंक में कार्यरत थे। घर पर उनकी पत्नी पूनम राज का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका बेटा शिवम राज बेंगलुरु में कार्य करता है, जबकि बेटी स्वर्णराज दिल्ली में कार्यरत है। पत्नी ने बताया कि मुझे सुबह टीवी में समाचार देखकर कुंभ मेला में भगदड़ होने की जानकारी मिली। इसके बाद मैंने अपने पति को काफी फोन लगाया। उनके साथ गए लोगों को भी फोन लगाया, परंतु किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। मैं घबराकर मेरे पति के साथ गए मुसाबनी में ही शास्त्री नगर के रहने वाले राज सिन्हा की पत्नी सीमा सिन्हा को फोन किया, तब उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हुई है। मेरी पति से आखिरी बार मंगलवार की रात लगभग 11 बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि यहां भीड़ काफी है। ट्रैफिक जाम होने के कारण हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी है। 21 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा के तट तक पहुंचना है। अब मात्र 1 किलोमीटर बचा है। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे और प्रातः स्नान करेंगे. इस घटना के बारे में पूनम सिन्हा से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि देर रात वहां अचानक भगदड़ हो गई, जिसमें सभी का एक दूसरे से हाथ छूट गया और शिवराज गुप्ता जमीन पर गिर गए, दबने और सांस रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि मंगलवार की रात 11 बजे बात करने के बाद उनसे संपर्क समाप्त हो गया। उनके साथ कुंभ स्नान के लिए गए अन्य लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे पति और अन्य 14 लोग 15 सीटर गाड़ी से 25 जनवरी की सुबह मुसाबनी से रवाना हुए थे। अयोध्या होते हुए मंगलवार को प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्हें स्नान करना था। मृतक शिवराज गुप्ता अपने पीछे पत्नी एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि बेटा व बेटी बेंगलुरु व दिल्ली से मुसाबनी आ रहे हैं। पति के साथ गए अन्य लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

घाटशिला की दो महिलाएं लापता

दूसरी ओर घाटशिला मुख्य शहर के भुजा व्यवसायी तारेकेश्वर साव अपनी पत्नी सुनैना देवी एवं उनके भाई राजेंद्र साव व उनकी पत्नी सरिता देवी 26 जनवरी को एक स्कार्पियों पर अन्य स्थानों के कुल 12 लोग के साथ कुंभ गए थे। इस दौरान वे लोग बनारस में रुकने के बाद मंगलवार को कुंभ पहुंचे। जब ये लोग कुंभ में पहुंचे, उसी दौरान भगदड़ मच गई। दोनों महिला का साथ इन लोगों से छूट गया। भगदड़ के शांत होने के बाद बाकी बचे 10 लोगों ने महिला को खोजना शुरू किया, लेकिन कहीं पता नही चला। इसके बाद प्रशासन का सहयोग लेकर इन लोगों ने एनाउंस भी कराया, जिसके बाद भी महिला नहीं मिली। इस घटना में घायल हुए लोग जिस-जिस अस्पताल में भर्ती हैं, वहां भी जाकर देखा गया, लेकिन महिला अभी तक नही मिली।

महाकुंभ में दिल का दौरा पड़ने से कैवल्यानंद महाराज का निधन

MANOHARPUR : प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बुधवार को ब्रह्मचारी कैवल्यानंद महाराज का हृदयगति रुकने से निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परम प्रिय शिष्य कैवल्यानंद विश्व कल्याण आश्रम काली कोकिला संगम, समीज पालीपीष, झारखंड के मुख्य प्रभारी थे। दिवंगत ब्रह्मचारी कैवल्यानंद बुधवार को प्रात: 9.45 बजे मनकामेश्रर मंदिर क्षेत्र सरस्वती घाट प्रयागराज में संगम स्नान के लिए जा रहे थे। संगम घाट जाने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर मनोहरपुर,आनंदपुर, गोईलकेरा सहित समीज आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई है।

ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव कराता गंडिकोटा

गंडिकोटा, आंध्र प्रदेश के सबसे खूबसूरत और अद्भुत पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे अक्सर दक्षिण का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। यह स्थान अपनी शानदार चट्टानों, सुंदर घाटियों और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं गंडिकोटा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में।

1. गंडिकोटा किला

गंडिकोटा का किला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भव्यता और ऐतिहासिकता का प्रतीक है। किले की दीवारें, मीनारें और दरवाजे अद्भुत वास्तुकला का नमूना हैं। यहाँ से घाटी का दृश्य बेहद सुंदर है।

2. कावेरी नदी

गंडिकोटा के निकट कावेरी नदी बहती है, जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ाती है। नदी के किनारे बैठकर लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। यहाँ की जलधारा और लहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

3. गंडिकोटा घाटी

गंडिकोटा घाटी अपने अद्भुत दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें और घाटियाँ फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन स्थान हैं। सूर्यास्त का दृश्य यहाँ से देखने लायक होता है।

4. रानी दुर्गा देवी का मंदिर

यह प्राचीन मंदिर गंडिकोटा में स्थित है और देवी दुर्गा को समर्पित है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की एक बड़ी संख्या होती है। मंदिर का वास्तुशिल्प और यहाँ का वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

5. जैन मंदिर

गंडिकोटा में एक प्राचीन जैन मंदिर भी है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की शिल्पकला और जैन मूर्तियाँ अद्वितीय हैं।

यात्रा की जानकारी

गंडिकोटा की यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जिद्दलूर है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचना आसान है। यह स्थान वर्ष भर में किसी भी समय यात्रा के लिए उपयुक्त है, लेकिन मानसून के बाद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है।

देखा जाये तो गंडिकोटा एक ऐसा स्थान है जहाँ आप ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ की चट्टानें, घाटियाँ और किला एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं या इतिहास के प्रति रुचि रखते हैं, तो गंडिकोटा आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। यहाँ की यात्रा निश्चित रूप से आपके मन में अद्भुत यादें छोड़ जाएगी।

ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है ओरछा

भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित ओरछा, एक ऐतिहासिक नगर है जो अपनी प्राचीन किलों, महलों, मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण पेश करता है। ओरछा न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, जो प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकिनों के लिए आदर्श स्थल है।

ओरछा का इतिहास

ओरछा का इतिहास 16वीं शताबदी से जुड़ा हुआ है, जब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेला राजवंश के राजा वीर सिंह देव द्वारा स्थापित किया गया था। राजा वीर सिंह देव ने यहां किलों, महलों, और मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी इस स्थल की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़े हैं। ओरछा, पहले बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था और इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक परिवर्तनों का साक्षी बनने का कार्य किया।

ओरछा के प्रमुख आकर्षण

ओरछा किला

यह किला ओरछा का प्रमुख आकर्षण है, जो नदियों और जंगलों से घिरा हुआ है। किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने 16वीं शताबदी में करवाया था। किले के भीतर राजमहल, छतरियां और मंदिर स्थित हैं। किले से ही ओरछा शहर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है।

छतरियां

ओरछा के किले के पास स्थित छतरियां बुंदेला राजाओं की समाधियाँ हैं। ये स्मारक नदी के किनारे बने हुए हैं और इनका वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। छतरियों के वास्तुशिल्प और उनके परिसर का दृश्य बहुत ही भव्य और शांतिपूर्ण होता है।

रामराजा मंदिर

रामराजा मंदिर ओरछा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ भगवान राम की एक अनोखी प्रतिमा स्थापित है, जो अन्य राम मंदिरों से भिन्न है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं।

जंगली महल

यह महल ओरछा किले के भीतर स्थित है और इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। जंगली महल की वास्तुकला, जिसमें मुग़ल और बुंदेला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, पर्यटकों को आकर्षित करती है।

लक्ष्मी मंदिर

यह मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है और अपनी भव्यता और सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ और चित्रण बहुत ही शानदार हैं।

चतुर्भुज मंदिर

यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर ओरछा के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है।

ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता

ओरछा न केवल ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आदर्श स्थल है। यहाँ की शांतिपूर्ण नदियाँ, घने जंगल, और हरे-भरे मैदान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे की सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। बेतवा नदी में बोटिंग करने का अनुभव भी एक अलग ही रोमांचक होता है।

इसके अलावा, ओरछा का मौसम भी काफी मनमोहक होता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुकून और शांति का अनुभव कराता है। सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों में यहाँ की यात्रा की जा सकती है, लेकिन सर्दी का मौसम (नवंबर से फरवरी) यहाँ यात्रा के लिए सबसे आदर्श समय माना जाता है।

ओरछा का सांस्कृतिक महत्व

ओरछा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ के मंदिरों और महलों में बुंदेला संस्कृति और वास्तुकला की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओरछा में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, जो यहाँ के लोक जीवन को दर्शाते हैं। यहाँ के मेलों और त्योहारों में शामिल होकर आप ओरछा की संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं।

ओरछा कैसे पहुंचे?

वायु मार्ग- ओरछा का नजदीकी हवाई अड्डा झाँसी है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से ओरछा पहुँचा जा सकता है।

रेल मार्ग- झाँसी रेलवे स्टेशन, ओरछा का नजदीकी रेलवे स्टेशन है और यह भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा ओरछा पहुँच सकते हैं।

सड़क मार्ग- ओरछा प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। झाँसी, ग्वालियर और कानपुर जैसे शहरों से यहां के लिए नियमित बस सेवाएँ उपलब्ध हैं।

ओरछा एक ऐसा स्थल है जहाँ आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देख सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, ऐतिहासिक किले, मंदिर और महल पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। अगर आप भारतीय इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो ओरछा की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी।

ओरछा का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेला राजवंश के राजा वीर सिंह देव द्वारा स्थापित किया गया था। राजा वीर सिंह देव ने यहां किलों, महलों, और मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी इस स्थल की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़े हैं।

साल 2025 में जरूर एक्सप्लोर करें ये बेहतरीन जगह, नए एक्सपीरियंस का मिलेगा मौका

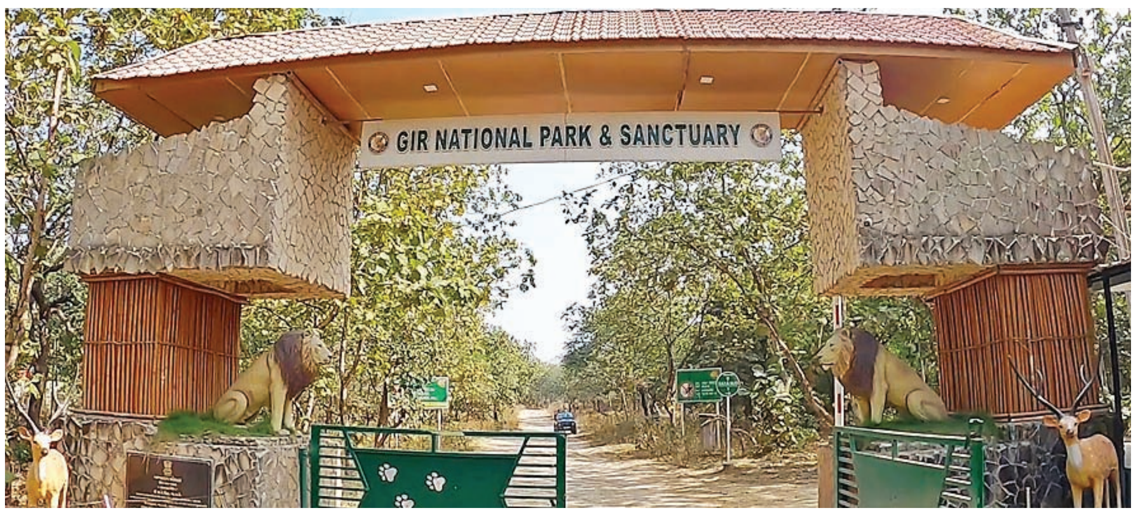

दुनियाभर में घूमने-फिरने में दिलचस्पी रखने वाले लोग हमेशा कहीं न कहीं की ट्रिप प्लान कर लेते हैं। फेमस पर्यटन स्थल हर किसी के पसंदीदा होते हैं। इन जगहों पर कभी पर्यटकों की कमी नहीं होती है। सालों से इन जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इस लिस्ट में विदेशी पर्यटक स्थल और देश के पर्यटक स्थल दोनों शामिल हैं। बता दें कि जो लोग शानदार प्राकृतिक नजारों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भारत पर्यटन स्थलों से समृद्ध देश है। यहां पर समुद्री तटों के विकल्प और ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हैं। हरे-भरे मैदानी क्षेत्र तो सफेद रेतीले मैदान भी हैं। आप जंगल सफारी से लेकर ऊंट सफारी और क्रूज से लेकर फैरी तक के सफर का आनंद उठा सकते हैं।

बता दें कि साल 2024 में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। साल 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों की संख्या में सैलानी अयोध्या पहुंचे। तो दूसरी ओर पीएम मोदी के आह्वान पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षदीप पर पर्यटकों की काफी संख्या बढ़ी। वहीं अब साल 2025 में भी कई पर्यटन स्थल लोकप्रिय हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी नए साल 2025 में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आज इस आर्टिकल के जरिए देश के पांच फेमस पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं।

आलाप्पुझा, केरल - अगर आप भी केरल की प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहते हैं, तो अलाप्पुझा जा सकते हैं। यहां पर आपको पारंपरिक हाउसबोट का अच्छा अनुभव मिलेगा। एलेप्पी के नाम से जाना जाने वाली यह जगह सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहां पर आप नवंबर से फरवरी के बीच घूमने आ सकते हैं। इस दौरान आप अलाप्पुझा बीच, वेम्बनाड झील, मारारी बीच, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य और पुन्नमदा झील के प्राकृतिक परिवेश का अनुभव करें। यहां पर रेवी करुणाकरण मेमोरियल म्यूजियम, सेंट मैरी चर्च और अलाप्पुझा लाइट हाउस का लुत्फ उठाएं।

जैसलमेर -जैसलमेर थार रेगिस्तान में बसा है, यह राजधानी की संस्कृति के साथ हमेशा बदलते टीलों और परंपराओं का अनुभव कराने के लिए एक परफेक्ट जगह है। प्राचीन बलुआ पत्थर की वास्तुकला, कभी न खत्म होने वाला रेगिस्तान और तेज धूप ने जैसलमेर को गोल्डन सिटी का खिताब दिया है। आप नवंबर से फरवरी के बीच इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर आप वुड फॉसिल पार्क, कुलधरा गांव, व्यास छतरी, जैसलमेर युद्ध संग्रहालय, जैसलमेर किला, कोठारी की पटवों की हवेली, गड़ीसर झील, नाथमल जी की हवेली और थार रेगिस्तान को घूम ने जा सकते हैं।

गिर नेशनल पार्क -गुजरात में गिर राष्ट्रीय वन के नाम से फेमस यह पार्क भारत में मैजेस्टिक एशियाई शेरों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह पार्क जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में फैला हुआ है। यह काठियावाड़-गुर शुष्क वन का हिस्सा है। नवंबर से मार्च तक का समय इस जगह को घूमने के लिए सबसे बेहतर है। यहां आप जंगल सफारी के जरिए 674 शेर, 300 तेंदुए और 425 पक्षियों की प्रजातियों में से कोई एक देख सकते हैं।

गोवा - समृद्ध पुर्तगाली संस्कृति, जीवंत नाइटलाइफ़ और शानदार समुद्र तट की वजह से गोवा साल भर घूमने के लायक है। साल 2025 में भी गोवा भारत में घूमने के लिहाज से सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वैसे तो गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का है। इस दौरान आप कलंगुट, अरम्बोल, अगोंडा, पणजी, कैंडोलिम, बागा, वागाटोर, कोल्वा, पालोलेम और वर्का की खोज करें। समुद्र तट पर मौज-मस्ती के अलावा कयाकिंग, सर्फिंग या स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से मिल सकती हैं कई सौगातें

प्रहलाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रेल-सितम्बर 2024) में भारत की आर्थिक विकास दर कुछ कमजोर रही है। प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2024) में तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इसी प्रकार द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2024) में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में मुख्य रूप से देश में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव है और आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भरकम कमी दृष्टिगोचर हुई है। साथ ही, देश में मानसून की स्थिति भी ठीक नहीं रही है।

केंद्र सरकार ने हालांकि मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने में सफलता तो अर्जित कर ली है परंतु उच्च स्तर पर बनी रही मुद्रा स्फीति के कारण कुल मिलाकर आम नागरिकों, विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों, की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभात जरूर पड़ा है और कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की श्रेणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रहती है, उस देश की आर्थिक विकास दर ऊंचे स्तर पर बनी रहती है क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए फ्लेट्स एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग करता है। इससे आर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं।

भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है अतः दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह

भी कहना है कि न केवल आय कर में बल्कि कारपोरेट कर में भी कमी की घोषणा की जानी चाहिए। इनफोसिस के संस्थापक सदस्यों में शामिल श्री मोहनदास पई का तो कहना है कि 15 लाख से अधिक की आय पर लागू 30 प्रतिशत की आय कर की दर को अब 18 लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। आय कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में लागू 7.75 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देना चाहिए। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत किए जाने निवेश की सीमा को भी 1.50 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रदान की जाने वाली आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए।

फरवरी 2025 माह में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पोलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे रेपो दर में कम से कम 25 अथवा 50 आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि, पिछले लगातार लगभग 24 माह तक रेपो दर में कोई भी परिवर्तन नहीं करने के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं चार पहिया वाहन आदि खरीदने हेतु बैंकों से लिए गए ऋण की किश्त की राशि का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। बैंकों से लिए गए इस प्रकार के ऋणों एवं माइक्रो फाइनैन्स की किश्तों की अदायगी में चूक की घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुद्रा स्फीति की दर खाद्य पदार्थों (फलों एवं सब्जियों आदि) के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर पर आ जाती है जबकि कोर मुद्रा स्फीति की दर तो अब नियंत्रण में आ चुकी है। खाद्य पदार्थों की मंहगाई को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक को अब इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते देश में पूंजीगत खर्चों में कमी दिखाई दी है। इसीलिए अब लगातार यह मांग की जा रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के चलते अपने बजटीय खर्चों को रोक दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोक सभा में पेश किए जाने वाले बजट में पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर गम्भीरता दिखाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 7.50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे देश में धीमी पड़ रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे, जिसकी वर्तमान समय में देश को अत्यधिक आवश्यकता भी है।

विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही फ्रीबीज की योजनाओं पर भी अब अंकुश लगाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन योजनाओं से देश के आर्थिक विकास को लाभ कम और नुक्सान अधिक होता है। केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली की स्थिति हम सबके सामने है। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने के कारण इन राज्यों के बजटीय घाटे की स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। पंजाब तो किसी समय पर देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में शामिल हुआ करता था परंतु आज पंजाब में बजटीय घाटा भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिससे ये राज्य आज पूंजीगत खर्चों पर अधिक राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की न तो आय बढ़ रही है और न ही बजटीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है।

पिछले कुछ समय से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। यह सितम्बर 2020 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत था जो अब गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019 के बजट में कोरपोरेट कर की दरों में कमी की घोषणा की गई थी, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पड़ा था और सितम्बर 2020 में तो यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब एक बार पुनः इस बजट में कोरपोरेट कर में कमी करने पर भी विचार किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। हां, साथ में तकनीकी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमारे उद्योगों को हमें प्रतिस्पर्धी बनाना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है अतः कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान इस बजट के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही निर्मित हों और नागरिकों के शहर की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।

संपादकीय

हंगामा कितना सही

वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की आखिरी बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। दस विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने के बाद बैठक सुचारू रूप से चली। भाजपा नेतृत्व वाले एनड़ीए के चौदह प्रस्ताव पारित कर दिए, जबकि विपक्ष के तरफ रखे सभी 44 प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड.से प्रस्तावित दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को हटाने के सुझाव प्रमुख थे, जिन्हें नामित करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। वक्फ संपत्ति पर विवाद होने पर कलेक्टर स्तर का अधिकारी जांच करेगा। यह कानून पिछले मामलों पर लागू नहीं होगा। जो वक्फ की संपत्तियां पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीकरण शुरू होगा। जिन संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है, वे वापस मालिकों को मिल सकेंगी। आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने प्रयास करेगा। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। वे संसद से मंजूरी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। जैसा कि भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति में सुराख करने व गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के नाम पर इसे कानून बनाने की मशक्कत लंबे समय से कर रही है। तमाम विरोधों के बावजूद कुछ लोग कब्रिस्तान में होने वाले अतिक्रमणों व जबरन की जा रही अनधिकृत कब्जेदारी से निजात पाने के लिए इस निर्णय से खुश भी हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन व प्रबंधन के उद्देश्य से संशोधन विधेयक 2024 को लेकर अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। अनुमान है कि 2009 में वक्फ के पास चार लाख एकड़.जमीन थी, जो आठ लाख एकड़.तक जा पहुंची है। इनमें कब्रगाहों के अतिरिक्त मदरसों व मस्जिदों की जमीनें बताई जाती हैं। हालांकि धारा 104ए पहले ही वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, किसी भी तरह के बंधन या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। मगर वक्फ को दिए गए अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार समुदाय विशेष के साथ पक्षपाती रवैया रखती है इसलिए उसके द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय संदेह से परे नहीं माने जाते। विपक्ष को अपनी बात सलीके से रखनी चाहिए परंतु उसकी अनसुनी किया जाना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। समिति को एकतरफा निर्णय लेने की बजाए मध्यमार्ग अपनाने के प्रति जबावदेह होना चाहिए।

चिंतन-मनन

जीना और मरना

जिस भांति हम जीते हैं, उसे जीवन नाममात्र को ही कहा जा सकता है। हमे न जीवन का पता है; न जीवन के रहस्य का द्वार खुलता है। न जीवन के आनंद की वष्रा होती है; न हम यह जान पाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, किसलिए जी रहे हैं? हमारा होना करीब-करीब न होने के बराबर होता है। किसी भांति अस्तित्व ढो लेते हैं, जीवित रहते हुए मुर्दे की भांति। लेकिन ऐसा भी होता है कि मरते क्षण में भी कोई जीवंत होता है कि उसकी मृत्यु को भी हम मृत्यु नहीं कहते। बुद्ध की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सकते हैं और अपने जीवन को हम जीवन नहीं कह पाते हैं। कृष्ण की मृत्यु को मृत्यु कहना भूल होगी। उनकी मृत्यु को हम मुक्ति कहते हैं। उनकी मृत्यु को हम जीवन से और महाजीवन में प्रवेश कहते हैं। उनकी मृत्यु के क्षण में कौन-सी प्रांति घटित होती है, जो हमारे जीवन के क्षण में भी घटित नहीं हो पाती। किस मार्ग से वे मरते हैं कि परम जीवन को पाते हैं। और किस मार्ग से हम जीते हैं कि जीवत रहते हुए भी हमें जीवन की कोई सुगंध का भी पता नहीं पड़ता है। जिसे हम शरीर कहें, वह हमारे लिए कब्र से ज्यादा नहीं है, एक चलती-फिरती कब्र। और यह लंबा विस्तार जन्म से लेकर मृत्यु तक, बस आहिस्ता-आहिस्ता मरते जाने का ही काम करता है। ऐसे रोज-रोज और मौत के करीब पहुंचते हैं। हमारी सारी यात्रा मरघट पर पूरी हो जाती है। जीने का सब कुछ निर्भर है जीने के ढंग पर और मरने का भी सब कुछ निर्भर है मरने के ढंग पर। हमें जीने का ढंग भी नहीं आता। बुद्ध जैसे व्यक्ति को मरने का ढंग भी आता है। कृष्ण ने कहा है, ।।हे अजरुन, जिस काल में शरीर त्यागकर गए योगीजन, पीछे न आने वाली गति और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को, उस मार्ग को मैं तुमसे कहूंगा। इसमें दो-तीन बातें समझ लेनी चाहिए। जिस काल में, जिस क्षण में। बड़ा मूल्य है क्षण का, बड़ा मूल्य है काल का। उस क्षण का जिसमें कोई व्यक्ति मृत्यु को उपलब्ध होता है।

महाकुंभ में भगदड़ : कुप्रबंधन या वीआईपी संस्कृति का दुष्प्रभाव?

डॉ हिदायत अहमद खान

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि को हुई भगदड़ की घटना वास्तव में बेहद ही दुःखद और हृदयविदारक है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं वहां भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक छोटी सी असावधानी या किसी गलती के कारण इस तरह की भगदड़ से कई निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली जाती है, जबकि अनेक लोग घायल हो इलाज के लिए अस्पताल का रुख करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुःखद घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। यह तो ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों होती हैं? कभी कोई अफवाह भगदड़ का कारण बनती है तो कभी अचानक कोई छोटी घटना बड़ी भगदड़ का कारण बन जाती है। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बड़ती संख्या और उस पर वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना भगदड़ का कारण बताया जा रहा है। यह सच है कि भीड़ भरे इलाकों में जब-जब वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, तब-तब आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कमी आ ही जाती है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर उपाय किए जाने की अक्सर सलाह दी जाती है, लेकिन एक चूक और आमजन की जान-जोखिम में पड़ जाती है, जैसा कि महाकुंभ के दौरान देखने में आया है। अतः ऐसी स्थिति में भीड़ नियंत्रण के साथ ही वीआईपी कल्चर वाले प्रबंधन पर भी विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और अनेक लोग घायल हो गए हैं, घायलों का उपचार प्रथम प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने घटना को लेकर गहरी संवेदनाएं और दुख जताया है वहीं हर बार की तरह, इस बार भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने तो विशेष रूप से, भीड़ प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट को लेकर गहरी चिंताएं जताई हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए भीड़ नियंत्रण को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से अधिक प्रशासन का ध्यान वीआईपी मूवमेंट पर रहता है, जिससे अव्यवस्था फैलती है। यहां राहुल गांधी ने बहुत सही कहा है कि वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाकर बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग भी की है कि आगे ऐसी घटनाएं न हों और आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। बात बहुत ही गंभीर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वीआईपी मूवमेंट को दरकिनार कर आमजन को सुविधाएं मुहैया कराए जाने पर कार्य किया जा सकता है? इसके लिए आमजन की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल बात है, लेकिन सरकार चाहे तो वीआईपी कल्चर पर रोक लगाते हुए खुद अपने स्तर पर जनसुविधाओं को बेहतर करने का काम कर सकती हैं। वीआईपी सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से आमजन की भीड़ को नियंत्रित करने की परंपरा है, उसे बदलना फिलहाल किसी के बूते की बात नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वीआईपी सदा से ही अपराध जगत के निशाने पर रहते आए हैं। ऐसे में अपराधी भीड़ का सहारा लेकर वीआईपी पर हमले करते रहे हैं और देश ने ऐसे ही हमलों में अपने हरदिल अजीज अनेक नेताओं को खोया भी है। इसलिए वीआईपी कल्चर बदलने से पहले देश में अपराध और अपराधियों को रोकने का माकूल इंतजाम करना होगा।

गांधी निर्वाण दिवसः अब बनने लगा है गांधी के सपनों का भारत

ललित गर्ग

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस जब हम नये भारत-सशक्त भारत को विकसित होते हुए देखते है तो प्रतीत होता है कि यह गांधी के ही सपनों का भारत बन रहा है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने गांधी की केवल मूर्तियां स्थापित की, लेकिन भाजपा सरकार अपनी नीतियों में गांधी दर्शन को लागू कर रही है। गांधी के अहिंसा दर्शन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल देश में बल्कि दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। गांधी की अहिंसा ने भारत को गौरवान्वित किया है, भारत ही नहीं, दुनियाभर में अब उनकी जयन्ती को बड़े पैमाने पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी महानायक के रूप में ही नहीं, देवनायक के रूप में लोकतंत्र के मजबूत आधार एवं संकटमोचक है। संसद से लेकर सड़क तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और व्यक्ति से लेकर विचार बनने तक जीवन के हर नीति में, हर दृष्टिकोण में, हर मोड़ पर गांधी की व्याप्ति है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर नये भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां हमारी हर सोच में, हर क्रियाएं में, हर नीति में गांधी का होना यह दर्शा रहा है कि आज गांधी पूर्व सरकारों की तुलना में ज्यादा जीवंत बने हैं।

महात्मा गांधी के विचार एवं दर्शन पर ही मोदी सरकार की योजनाएं एवं नीतियां आगे बढ़ रही है। इस बात का खुलासा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए कहा है कि उनके सबका साथ, सबका विकास के विचार की प्रेरणा 1980 के दशक की है। मोदी ने अपने हाथ से लिखे एक नोट्स में इस विचार के बारे में काफी पहले ही लिख दिया था। मोदी द्वारा लिखे गए नोट्स से पता चलता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिसमें युवा मोदी ने महात्मा गांधी के विचारों उद्धरत करके लिखा था, मैं सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी भलाई के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। यह 51 प्रतिशत की अच्छाई के लिए 49 प्रतिशत की भलाई का त्याग करना है। यह सिद्धांत एक क्रूर सिद्धांत है। इसके माध्यम से मानवता को काफी नुकसान हुआ है। मानवता के लिए एक मात्र सिद्धांत है कि सभी के लिए भलाई के काम में विश्वास करना।ह्ल मोदी सरकार सभी की भलाई के लिये काम करते हुए गांधी दर्शन को ही आगे बढ़ा रही है।

मोदी का स्वच्छता मिशन गांधी की स्वच्छता सोच को ही आगे बढ़ाने का उपक्रम है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भी गांधी के नाम पर चल रही योजना है। भारतीय मुद्रा से लेकर शासन-प्रशासन के हर कार्यस्थल पर गांधी है। हम गांधी के संवाद और सहिष्णुता के सिद्धान्तों को अपनाते हुए युद्ध, आतंकवाद और हिंसा को निस्तेज बना रहे हैं। दलित-आदिवासियों को न्याय और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदत्त कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जुटे हैं। भारत माता, गौ माता और गंगा माता के सांस्कृतिक एवं धार्मिक चिन्तन को आगे बढ़ाते हुए गांधी की मूल अवधारणा को ही आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज गांव, गरीब और स्वराज में गांधी की ही सोच आगे बढ़ रही है कि आज भारत में लोकतंत्र की चाल, चेहरा और चरित्र बदला जा रहा है तथा आस्थाओं की राजनीति को बल देते हुए जाति-धर्म का उन्माद नियंत्रित किया जा रहा है। महात्मा गांधी, आंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय आज इसलिए भारत निर्माण की नई व्याख्याओं में सबसे आगे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम एवं सर्वधर्म सद्भाव का विचार आज सर्वाधिक बलशाली बन कर दुनिया के लिये आदर्श बन गया है।

मानव ने ज्ञान-विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति की है। परन्तु अपने और औरों के जीवन के प्रति सम्मान में कमी आई है। विचार-क्रान्तियां बहुत हुईं, किन्तु आचार-स्तर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन कम हुए। शान्ति, अहिंसा और मानवाधिकारों की बातें संसार में बहुत हो रही हैं, किन्तु सम्यक्-आचरण का अभाव अखरता है। गांधीजी ने इन स्थितियों को गहराई से समझा और अहिंसा को अपने जीवन का मूल सूत्र बनाया। यदि अहिंसा, शांति और समता की व्यापक प्रतिष्ठा नहीं होगी तो भौतिक सुख-साधनों का विस्तार होने पर भी मानव शांति की नींद नहीं सो सकेगा। महात्मा गांधी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में नरेन्द्र मोदी हमारे सामने हैं, उनके प्रभावी एवं चमत्कारी नेतृत्व में हम अब वास्तविक आजादी का स्वाद चखने लगे हैं, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद की कालिमा धूल गयी है, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर भी नियंत्रण हो रहा है। इन नवनिर्माण के पदचिन्हों को स्थापित करते हुए हम गांधी को जीवंत बनाये हुए है, यही कारण है कि कभी हम स्कूलों में शोचालय की बात सुनते है तो कभी गांधी जयन्ती के अवसर पर स्वयं झाडू लेकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए मोदी को देखते हैं। मोदी कभी विदेश की धरती पर हिन्दी में भाषण देकर राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते है तो कभी ह्लमेक इन इंडियाह्व का शंखनाद कर देश को न केवल शक्तिशाली बल्कि आत्म-निर्भर बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। नई खोजों, दक्षता, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा की रक्षा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन, श्रेष्ठ का निर्माण-ये और ऐसे अनेकों गांधी के सपनों को आकार देकर सचमुच लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता को सुदीर्घ काल के बाद सार्थक अर्थ दिये जा रहे हैं।

हम देशवासियों के लिये अपूर्व प्रसन्नता की बात है कि गांधी की प्रासंगिकता चमत्कारिक ढंग से बढ़ रही है। देश एवं दुनिया उन्हें नए सिरे से खोज रही है। उनको खोजने का अर्थ है अपनी समस्याओं के समाधान खोजना, युद्ध, हिंसा एवं आतंकवाद की बढ़ती समस्या का समाधान खोजना। शायद इसीलिये कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारों को पढ़ाया जा रहा है, उन पर शोध हो रहे हैं। आज भी भारत के लोग गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए अहिंसा, शांति, सह-जीवन, स्वदेशी का समर्थन करते हैं। गांधीजी आज संसार के सबसे लोकप्रिय भारतीय बन गये हैं, जिन्हें कोई हैरत से देख रहा है तो कोई कौतुक से। इन स्थितियों के बावजूद उनका विरोध भी जारी है। उनके व्यक्तित्व के कई अनजान और अंधेरे पहलुओं को उजागर करते हुए उन्हें पतित साबित करने के भी लगातार प्रयास होते रहे हैं, लेकिन वे हर बार ज्यादा निखर कर सामने आए हैं, उनके सिद्धान्तों की चमक और भी बढ़ी है। वैसे यह लम्बे शोध का विषय है कि आज जब हिंसा और शस्त्र की ताकत बढ़ रही है, बड़ी शक्तियां हिंसा को तीक्ष्ण बनाने पर तुली हुई हैं, उस समय अहिंसा की ताकत को भी स्वीकारा जा रहा है।

यह बात भी थोड़ी अजीब सी लगती है कि पूंजी केन्द्रित विकास के इस तूफान में एक ऐसा शख्स हमें क्यों महत्वपूर्ण लगता है जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की वकालत करता रहा, जो छोटी पूंजी या लघु उत्पादन प्रणाली की बात करता रहा। सवाल यह भी उठता है कि मनुष्यता के पतन की बड़ी-बड़ी दास्तानों के बीच आदमी के हृदय परिवर्तन के प्रति विश्वास का क्या मतलब है? जब हथियार ही व्यवस्थाओं के नियामक बन गये हों तब अहिंसा की आवाज कितना असर डाल पाएगी? एक वैकल्पिक व्यवस्था और जीवन की तलाश में सक्रिय लोगों को गांधीवाद से ज्यादा मदद मिल रही है।

आज जबकि समूची दुनिया में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, हर कोई विकास की दौड़ में स्वयं को शामिल करने के लिये लड़ने की मुद्रा में है, कहीं सम्प्रदाय के नाम पर तो कहीं जातीयता के नाम पर, कहीं अधिकारों के नाम पर तो कहीं भाषा के नाम पर संघर्ष हो रहे हैं, ऐसे जटिल दौर में भी संघर्षरत लोगों के लिये गांधी का सत्याग्रह ही सबसे माकूल हथियार नजर आ रहा है। पर्यावरणवादी हों या अपने विस्थापन के विरुद्ध लड़ रहे लोग, सबको गांधीजी से ही रोशनी मिल रही है। गांधी की अहिंसा से सहयोग, सहकार, सहकारिता, समता और समन्वय जैसे उत्तम व उपयोगी मानवीय मूल्य जीवन्त हो रहे हैं। समस्त समस्याओं का समाधान भी एक ही है, वह है- अहिंसा। अहिंसा व्यक्ति में ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह्व की विराट भावना का संचार करती है। मनुष्य जाति युद्ध, हिंसा और आतंकवाद के भयंकर दुष्परिणाम भोग चुकी है, भोग रही है और किसी भी तरह के खतरे का भय हमेशा बना हुआ है। मनुष्य, मनुष्यता और दुनिया को बचाने के लिए गांधी से बढ़कर कोई उपाय-आश्रय नहीं हो सकता।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

26/11 probe gets a new lease of life

It is an irony that the US has decided to extradite Canadian national Tahawwur Hussain Rana to India for his supporting role in the Mumbai terror attacks that killed 166 people in November 2008, but has refused to part with one of the primary perpetrators — Daood Gilani aka David Coleman Headley. Rana, a doctor who had deserted from the Pakistan Army, and Headley were old friends and classmates at the Hassan Abdal military academy near Islamabad. Both were tried on 12 counts by a US court and sentenced to 15 and 35 years in jail, respectively, in 2013.etails of the Rana-Headley connection come to us from their indictment and trial in the US on terrorism charges. These were confirmed by the interrogation report of Headley by the National Investigation Agency in June 2010.In September 2023, the Mumbai police filed a 400-page supplementary chargesheet that came up with a surprise revelation: Rana had visited Mumbai a week ahead of the attacks. The US court documents did not have this information, which suggest that he may have had a more sinister role to play in the attacks.Rana came into the picture when Headley met him in Chicago in 2006 and told him about his Lashkar-e-Taiba (LeT) links and his decision to change his name to conceal his identity. He also told him about his association with Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) and his assignment to conduct surveillance in Mumbai. He asked Rana whether he could set up a branch of his First World Immigration office there, and Rana agreed.

After subsequent visits in 2007 and 2008, Headley kept Rana abreast of his activities there, including video surveillance of Taj Mahal hotel and surveying a possible landing site. He also briefed him on his conversations with Sajid Mir and Major Iqbal, two Pakistani ISI operatives. At least twice in his five visits to Mumbai, Headley received money from Rana at a bank close to the Oberoi hotel.Count 12 of the US indictment noted that since 2005, the two had "knowingly provided" material support — personnel, currency, tangible property, and false documentation and identification — to the LeT.

Despite this, Rana was actually acquitted on the counts relating to the Mumbai attacks. His conviction was on count 11 connected to the subsequent plot, of which Headley was also a part, to target Danish newspaper Jyllands-Posten and on count 12 for providing material support to terrorists.Rana's defence counsel claimed that he was "easily the least culpable of all the members of the plot". But there are many gaps in the American proceedings and this is what the Indian authorities hope to fill after they obtain Rana's custody.

Headley was not extradited to India because of his plea agreement with the US, which barred a death sentence and extradition to either India or Denmark. The US authorities said they were provided significant information by him about the association and the involvement of the ISI in the attacks, about the personnel, structure, methods, abilities and plans of the LeT, and that his testimony helped convict Rana and that he had also answered the questions of Indian authorities for seven days. In addition, Headley's actions also enabled the authorities to file criminal charges against six others — Sajid Mir, Abu Qahafa, Mazhar Iqbal, Major Iqbal, Ilyas Kashmiri and Abdur Rehman Hashim Syed.Rana did not enter a plea deal or fully cooperate with US authorities, and hence his extradition is taking place, albeit after a lengthy process. India did make efforts to extradite Headley. A request was sent to the US in December 2012 by the government, but despite this, America refused.There is no easy closure on 26/11. Though Lashkar chief Hafiz Saeed is serving a 78-year sentence for terror financing and his deputy Zaki-ur-Rehman Lakhvi and Rana are serving a 15-year jail term for terrorism, the whereabouts of other perpetrators — Sajid Mir, Abu Qahafa, Mazhar Iqbal, Major Iqbal, Hashim Syed, Muzammil and Zarrar Shah — are not very clear.s

Why UGC fondness for Governors is unhealthy

The role of state governments in the appointment of VCs has been eliminated, though education is a state subject and under the Concurrent List.

First formulated in 2010 and amended from time to time since then, the University Grants Commission (UGC) has again revised its rules on the "minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for maintenance of standards in higher education."The draft regulations 2025 have triggered a mixed response from academic circles as the intended modifications in certain contentious issues have far-reaching consequences on appointments, service conditions and promotions of teachers as well as the autonomy and control of the state on higher educational institutions (HEIs).With the aim of achieving the goals of National Education Policy (NEP) 2020, emphasis has been laid on the use of Indian languages, societal engagement and teaching, learning and research in the Indian knowledge system. The numerical score-based academic performance indicator (API) system for the recruitment and promotions of teachers has been replaced with a subjective evaluation system that involves contributions towards teaching, research and digital content creation. This system has inherent limitations, which have been already experienced prior to the API system era. Emphasis has been laid on non-measurable accomplishments, to be considered by selection committees. The new system lacks transparency, leaves room for irrational evaluation and manipulation, which is of serious concern.Apparently envisioned to promote academic flexibility, allowing teachers to teach subjects based on their highest specialisations without having degrees in the same subjects at the lower academic levels may create problems in case of collaborative multi-disciplinary studies and discourage the much-needed interdisciplinary research approaches.The draft document lacks a transparent mechanism for foolproof and acceptable implementation of its provisions to eliminate suspicion, partiality and undue preference to subjective evaluations.It is feared that de-capping of the limit on contractual appointments of teachers will encourage this practice, compromising the quality and creation of committed and innovative professionals. Such appointments need to be curtailed as they are only an emergent temporary solution.The minimum qualifications and procedure for the selection of vice-chancellor (VC) have been revised. Now, absolute powers are vested in chancellors (governors in case of state universities) to select VCs through search-cum-selection committees. The VC's post has also been opened for non-academicians from the industry, public administration and public policy. This is a cause of disappointment and discouragement for distinguished and accomplished

academicians.These ill-conceived, unsustainable solutions have probably been envisioned due to the recent rows between some opposition-ruled state governments and their governors over the appointment of VCs.The role of state governments in the appointment of VCs has been eliminated though, constitutionally, education is a state subject and under the Concurrent List.Being contrary to the federal principles of governance, the Tamil Nadu and Kerala governments have rejected the draft document. The document is also unacceptable to the All-India Federation of University and College Teachers Organisation. Some other quarters may also oppose it.Views have been expressed against making the VC's post open to non-academicians. Questions like whether we appoint businessmen as civil surgeons have been raised in this context. A VC is essentially an academic leader and scholastic role model for the faculty, staff and students.The HEIs are neither factories nor business franchises. They are institutions where excellence in teaching and learning is ensured and young minds are groomed for free thinking in a research-undertaking environment. These values cannot be appreciated by non-academic paratroopers or persons not exposed to the rigorous academic ecosystem of HEIs and lacking in academic and research knowledge and orientation, no matter how expert they may be in their field of specialisation.

It will open the VC's post to persons with political and ideological affiliations, compromising the eminence, propriety and commitment to academic excellence that is expected from this position. The appointment of non-academicians as Professors of Practice in universities with similar expectations, too, is yet to show tangibly beneficial results.

It would be in the interest of the nation to avoid such experimentations with HEIs. A balance of the role of state governments and governors in the selection of VCs is needed. Further, it should be provided that none of the selection committee members is below the rank of a VC; that a non-academician is not appointed VC even as a stop-gap arrangement; and that the post does not stay without a regular VC for a long time.Instead of inviting applications, nominations may be invited from current and former VCs, directors of institutions of importance, acclaimed intellectuals, etc, elucidating the achievements, integrity and calibre of the aspirant.

Though questionable, the draft regulations are mandatory in nature and impose stringent penalties on their violations. The penalties include debarring the institution from getting UGC schemes and disqualifying it not only from offering any degree but also the institution as a whole.

hese regulations, ostensibly asserted as "measures for maintenance of standards in higher education", are, in fact, a blatant effort to erode the autonomy of universities, impose Central control, compromise the quality of education, curtail academic freedom, undermine academicians and overstep the UGC mandate. The UGC Act of 1956 does not clearly contain any provision related to VCs' selection. Having no regulation till 2010, introducing the UGC nominee on the search panel in 2010, withdrawing it in 2013, reintroducing it in 2018 and expanding it for greater control over HEIs in 2025 reflects that the UGC itself is not clear about its role in VCs' appointments.The regulations will lead to academic chaos and put the state universities in a disadvantageous position. The UGC must not go ahead with the disruptive revisions.

Especially so, when the formation of an umbrella organisation — the Higher Education Commission of India (HECI) — as envisaged in NEP-2020, subsuming the UGC, is in the pipeline. The HECI would have responsibilities, like maintaining academic standards and specifying the eligibility criteria and mode for selection of VCs.

MGNREGS funds

Annual crunch demands urgent fixes

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), a lifeline for rural livelihoods, is once again grappling with an acute fund shortage. For the fiscal year 2024-25, the government allocatedRs 86,000 crore, yet Rs 4,315 crore worth of wage payments remain pending. In 2023-24, the scheme ran a deficit of

Rs 6,146 crore just six months into the year. Similarly, in 2022-23, the revised allocation of Rs 89,400 crore was 33 per cent higher than the original budget. This annual struggle to meet financial requirements raises critical questions about the scheme's implementation and funding priorities. It is riddled with glaring inefficiencies. The Congress' demand for increasing MGNREGS wages to Rs 400 per day reflects political optics rather than a sustainable solution. It is a popular move and fails to address the root cause: a systemic shortfall in timely fund

allocation.The Mahatma Gandhi National Rural

Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), a lifeline for rural livelihoods, is once again grappling with an acute fund shortage. For the fiscal year 2024-25, the government allocatedRs 86,000 crore, yet Rs 4,315 crore worth of wage payments remain pending. In 2023-24, the scheme ran a deficit ofRs 6,146 crore just six months into the year. Similarly, in 2022-23, the revised allocation of Rs 89,400 crore was 33 per cent higher than the original budget. This annual struggle to meet financial requirements raises critical questions about the scheme's implementation and funding priorities. It is riddled with glaring inefficiencies. The Congress' demand for increasing MGNREGS wages to Rs 400 per day reflects political optics rather than a sustainable solution. It is a popular move and fails to address the root cause: a systemic shortfall in timely fund allocation.

Fight for the eyesight of premature babies

Using unmonitored, high-concentration supplemental oxygen in newborn care units undoubtedly saves lives, but often at the cost of blindness.

Oxygen is the elixir of life, and this was brought home during the Covid-19 pandemic when millions of lives perished because of the worldwide scarcity of the much sought-after oxygen cylinders. However, it is not widely known that oxygen is also a double-edged sword. When given to yet-not-fully-developed babies born too soon, high-concentration oxygen may devastate their eyesight.

An estimated 18,000 babies thus go blind for life every year in India alone. Using unmonitored, high-concentration supplemental oxygen in newborn care units undoubtedly saves lives, but often at the cost of blindness. The blindness results from the consequences of scarring and unfettered growth of abnormal blood-supplying vessels in the immature retina. It is now known as retinopathy of prematurity (ROP).Babies mature in the womb for 40 weeks before entering the world. The eye's light-sensitive layer, the retina, is fully matured only if the baby attains at least 2,000-gm weight. If born before 31 weeks, several vital organs, especially lungs and retina, are not fully developed. A vast swath of the retina remains without a blood supply, especially in babies weighing less than 1,250 gm.Around the turn of the 20th century, doctors realised that babies born too soon could be saved if given oxygen. In the early 1940s, Dr Theodore Terry from Boston (USA) first flagged the issue of a visible white reflex due to massive scar tissue seen in the eyes weeks after birth of premature babies, all of whom weighed less than three pounds at birth. For several years, exposure to light was wrongly blamed.

It was a pathologist in London, Norman Ashton, who fortuitously discovered that the retina of the kitten till three weeks of birth was similar to that of a human baby born too soon. He created an ROP-like picture by first exposing these kittens to high-concentration oxygen and returning them to room air. Arnall Patz at Johns Hopkins was to discover almost simultaneously that if oxygen delivery in premature babies was monitored, they did not develop ROP.According to Dr Sourabh Dutta, Professor at the

Neonatology Department, PGI, Chandigarh, India is experiencing an epidemic of ROP-induced blindness due to increased survival of premature babies, unregulated oxygen use, lack of pulse oximeters and oxygen blenders in the newborn care units mushrooming all over urban India. Highly skilled manpower is required to care for these babies and counsel the parents. Although at-risk babies continue to be born, albeit in small numbers, in high-income countries of Europe, North America and Southeast Asia, hardly a baby goes blind from ROP because of the advanced infrastructure in the neonatal intensive care unit (NICU).Almost four decades after what led to ROP was understood, experts reached a consensus on grading the stage and severity of ROP and developed guidelines for treating the immature retina in these babies. While many early-stage cases resolve without treatment, some babies may require laser therapy or injections into the eye of drugs to block the abnormal retinal vessel development. If treated appropriately, success rates exceed most medical procedures. This protocol has also become the most cost-effective procedure by saving sight for the rest of life.Dr Joy Lawn from the London School of Hygiene and Tropical Medicine and colleagues estimated that nearly 15 million babies worldwide are born too soon (less than 37 weeks). With India topping the charts, almost eight million babies are born too soon in resource-limited middle- and low-income countries. Those born too soon in low-income countries with poor resources barely have any chance of survival.

Timely detection, staging and treatment within 48 hours of at-risk babies is the key to saving their sight. The American Academies of Paediatrics and Ophthalmology recommend screening babies born with a birth weight of less than 1,500 gm, gestational age of 30 weeks or less, or any newborn with a higher weight (up to 2,000 gm) who received oxygen even for a few days.Dr Praveen Kumar, head of the Neonatology Department in PGI, however, recommends that Indian babies born before 34 weeks or weighing less than 2,000 gm or even higher if oxygen support is required must be screened for ROP. Starting at 28 days of age or discharge from NICU, whichever is earlier, the eye surgeon needs to monitor the newborn until the retina is fully matured. Training thousands of eye surgeons and equipping them with the necessary skills nationwide to screen and treat these tiny babies is a herculean task. Dr Subhadra Jalali in Hyderabad and Anand Vinekar in Bangalore, both PGI alumni, have devoted their careers to saving the right of sight of these hapless babies.More than 50 years ago, Prof ON Bhakoo set up a modern neonatal intensive care unit (NICU) in the PGI, Chandigarh, and started training super specialists (DM) in neonatology. They were successful in saving the lives of very low birth weight babies. I remember Dr Anil Narang, who trained at Oxford and followed Professor Bhakoo, asking me the big question — who among us would undertake the onerous task of examining and treating those at risk of ROP in these tiny incubator-bound babies?

Dr Mangat Dogra, fresh from his training in the US, volunteered. As they say, the rest is history. Applying a cold probe at -80° Celsius (cryotherapy) to the retina that lacked blood supply was the standard of care back then if these babies had to have any eyesight in their lifetime. The babies had to be put under general anaesthesia. I remember the long hours he spent in NICU, examining babies, selecting those requiring treatment, and chasing anaesthetists, who, in those days, had little experience in giving anaesthesia to 1,000-1,200-gm babies. He would regularly share the day's story with me. I remember the pride on his face, a million-watt smile, announcing that the baby would see as the ROP had regressed.Over the decades, cryotherapy was supplanted with lasers and injections that do not require anaesthesia. In the last 35 years, Dr Dogra has treated the retinas of hundreds of premature babies and trained many ophthalmologists across India, including Anand. Happily, many of the same teeny-weeny babies he saved the sight are having babies with normal sight.

Dutch airline KLM scraps 250 jobs in cost-cutting drive

The Hague. Dutch airline KLM said Wednesday it was shelving 250 jobs as part of cost-cutting efforts it hopes will lead to a boost in operating profit of around 450 million euros ($469 million).

The firm said it would try to avoid forced lay-offs to achieve the cuts, but admitted it could not rule that out.The 250 jobs would come from "non-operational" roles, said KLM chief executive Marjan Rintel in a statement.

"It is crucial for our future to structurally lower costs, which involves making painful choices," said Rintel.

Other cost-cutting measures already announced by KLM include postponing the construction of a new HQ, as well as other maintenance buildings.The firm is also seeking to shelve non-core activities and bolster productivity by at least five percent, via automation, mechanisation and reducing absenteeism.KLM, allied with Air France, together posted a sharp drop in net profit for the third quarter of last year.

The Franco-Dutch group reported a profit after tax of 824 million euros, down 13 percent from the same three-month period last year.

Sebi rejects Danny Gaekwad's offer to buy 26% in Religare

NEW DELHI. Sebi has rejected the competing open offer for Religare Enterprises by Florida, US-based investor Digivijay 'Danny' Gaekwad.

Market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) responding to the Gaekwad's letter has said: "The letters submitted by Digvijay Laxmansinh Gaekwad are being returned since the same is not an exemption application in terms of Regulation 11 of SEBI (SAST) Regulations, 2011." The content of the letter was part of an exchange filing by the New Delhi-headquartered company.Gaekwad on January 24 had made a counter offer in cash for the company at Rs 275 a share as against Rs 235 apiece made by the Burman Family of the FMCG major Dabur group.

The offer was made in a letter addressed to the Chairperson of the market regulator, according to a filing made by Religare to the BSE.Gaekwad, in the letter, had said its offer of Rs 275 per equity share represents a 17% premium to the open offer price offered by the Burmans and a 24% premium to the 60-day volume weighted average price of Religare's shares calculated with a reference date of September 22, 2023, of Rs 221.We believe that the Burmans' Open Offer price of Rs 235 per equity share grossly undervalues the real worth of Religare and is to the detriment of public shareholders.At the time the offer was made on September 25, 2023, the offer price was already at a discount of 15% to Religare's prevailing market price of nearly Rs 271 per share. Even considering the closing price of Religare shares on January 22, 2025, the Burmans' Open Offer price is at a steep discount of 7%," the letter stated.

Maruti Suzuki approves reappointment of Hisashi Takeuchi as MD & CEO

New Delhi Maruti Suzuki India Ltd on Wednesday said its board has approved the reappointment of Hisashi Takeuchi as Managing Director and Chief Executive Officer for a further period of three years with effect from April 1, 2025.

The board in its meeting held on January 29, 2025 approved the appointment of Takeuchi as MD and CEO for a further period of three years till March 31, 2028, Maruti Suzuki India said in a regulatory

filing.Takeuchi was first appointed as Managing Director and Chief Executive Officer with effect from April 1, 2022, consequent to the completion of the term of his predecessor Kenichi Ayukawa on March 31, 2022.He has been on the Board of Maruti Suzuki since July 2019 and was Joint Managing Director (Commercial) from April 2021 till his elevation.

Budget 2025 income tax: Why standard deduction should be hiked under new tax regime

NEW DELHI. Budget 2025 income tax expectations: With Finance Minister Nirmala Sitharaman set to deliver the Union Budget 2025 speech on February 1, 2025, salaried and middle class taxpayers are looking to the Modi 3.0 government for income tax relief, especially under the new income tax regime.

The new income tax regime, introduced in FY 2020-21, has steadily seen changes with more favourable income tax slabs and rates, introduction of standard deduction and benefits for NPS. In Budget 2024, FM Sitharaman announced a hike of Rs 25,000 in standard deduction from Rs 50,000 to Rs 75,000 under the new income tax regime. The standard deduction under the old income tax regime, however, continues to be the same at Rs 50,000.Standard deduction is a flat deduction available on the salary income that helps reduce the taxable income of a taxpayer. With the new income tax regime being the default tax regime, and the government pushing for its adoption, taxpayers are looking to FM Sitharaman to increase the standard deduction limit further.

Budget 2025: Why standard deduction should be hikedPersonal tax experts are of the view that since no major exemptions and deductions are available under the new income tax regime, there is a strong case to hike the standard deduction to encourage further adoption. One expert even recommends considering standard deduction as a fixed percentage of income.Sundeep Agarwal, Partner, Vialto Partners says, "With rising living costs, the standard deduction under the new tax regime should be increased from Rs 75,000 to Rs 1,00,000. This hike would make the new income tax regime more attractive, considering no other deductions/exemptions are allowed."

According to Agarwal, raising the standard deduction would provide relief across income groups while keeping the tax system simple. "It would enhance disposable income, stimulate spending, and support economic growth while addressing inflationary pressures," he tells TOI.Kuldip Kumar, Partner,

Mainstay Tax Advisors LLP also believes that raising the standard deduction from Rs 75,000 to Rs 100,000 could provide relief to the salaried class."There is merit in this demand, as professionals/businesspeople can claim actual expenses incurred against the income they earn from their profession/business. Even those eligible for presumptive taxation benefit from a large amount of assumed expenditure, as a much lower amount is presumed to be their income for taxation purposes," he tells TOI."In comparison, salaried class taxpayers under the new tax regime have no deductions available, except for the standard deduction or the employer's contribution to the NPS. This does not result in equitable treatment for salaried taxpayers compared to others," he adds.

Sudhakar Sethuraman, Partner, Deloitte India says that the government can also consider providing standard deduction as a fixed percentage to the income like that of standard deduction of 30% on rental income. "Allocating fixed percentage brings equity across various income levels," he tells TOI.Surabhi Marwah, Tax Partner, EY India says that since there are no major deductions or exemptions available under the new tax regime, there is a strong case for increasing the standard deduction further to make the new tax regime attractive. "An increase could potentially lower taxable income, providing significant relief, particularly for individuals in lower to middle-income brackets," she says.Tax experts are also of the view that any further hike in standard deduction under the old income tax regime is unlikely since the government is looking to encourage adoption of the new income tax regime.

Zepto moves corporate base from Singapore to India ahead of IPO

NEW DELHI. Quick-commerce unicorn Zepto has officially moved its corporate base from Singapore to India, ahead of its highly anticipated initial public offering (IPO). The company's chief financial officer (CFO) Ramesh Bafna said that this is a good "ghar wapasi" template for the startup ecosystem and overtime, enables a great pipeline towards capital markets.

"Historic scenes on completion of… reverse merger from Singapore to India in the fastest ever timeline," Bafna said in a LinkedIn post today (January 28). "This is a display of understanding of technicals, working with right partners, getting into (the) nuts and bolts on execution, unblocking natural causes of delay and tactical calls real time by an empowered team," he added.Zepto's move follows a growing trend among Indian startups, including companies like Groww and PhonePe, that have shifted their headquarters back to India to tap into the expanding local startup ecosystem. The relocation also comes amid reports that Zepto is looking to increase the size of its IPO from the

previously planned $800 million to $1 billion.As part of its shift, Zepto's Mumbai-based entity, Kiranakart Technologies Private Ltd, will likely become the holding company for Zepto, according to a January 9 ruling by the National Company Law Tribunal (NCLT). Prior to this, Kiranakart Pte Ltd, based in Singapore, was the parent company.

Financially Zepto's revenue surged in financial year 2023-24, more than doubling to Rs 4,454.52 crore, up from Rs 2,025.70 crore the previous year.

The company's CFO Ramesh Bafna said that this is a good "ghar wapasi" template for the startup ecosystem and overtime, enables a great pipeline towards capital marketsZepto's move follows trend among Indian startups, including Groww and PhonePe that have shifted headquarters to India

Bajaj Auto share price rises 5% after Q3 results: Buy, hold or sell

NEW DELHI. Shares of Bajaj Auto shares rose sharply in early trade on Wednesday as investors reacted positively to the company's Q3FY25 results.

The two-wheeler company's stock rose over 5% to hit a day's high of Rs 8,803.70 on the Bombay Stock Exchange (BSE). At around 12:27 pm, shares of the company were trading 3.70% higher at Rs 8,702.90.Bajaj Auto posted a 3% year-on-year (YoY) increase in standalone net profit for the December quarter. Net profit stood at Rs 2,109 crore, while revenue from operations grew 6% YoY to Rs 12,807 crore. On a sequential basis, profit after tax (PAT) rose 5% from Rs 2,005 crore in the September quarter, though revenue fell 2% quarter-on-quarter.It may be noted that the YoY revenue growth was supported by strong exports and gains from the domestic green energy segment. Earnings before interest, tax, depreciation, and amortization (EBITDA) rose 6% YoY to Rs 2,581 crore, with operating margins improving 10 basis points to 20.2%.

Overall, Bajaj Auto's volumes grew 2% YoY to 12.24 lakh units, with exports playing a key role in offsetting domestic market weakness.

WHAT DO BROKERAGES SAY?

Brokerage firm Nuvama maintained a 'Buy' rating on the stock with a target price of Rs 10,700. The brokerage highlighted better-than-expected EBITDA, supported by pricing, scale, PLI incentives, and cost management.Analysts at the brokerage expect export growth of over 20% and domestic growth between 6-8%, with revenue and EBITDA likely to grow at a CAGR of 11% and 12%, respectively, over FY25-27E.On the other hand, Axis Capital retained a 'Sell' rating, cutting its target price to Rs 7,550 from Rs 8,000.While exports are improving, the brokerage noted that Bajaj Auto lost over 100 basis points in market share over the first nine months of FY25. Lower volume assumptions led to a 7% cut in its EPS estimates for FY25-27E.

Pace of AI development 'terrifying,' says former safety researcher at OpenAI

NEW DELHI. A former safety researcher at OpenAI says he is "pretty terrified" about the pace of development in artificial intelligence, warning the industry is taking a "very risky gamble" on the technology, The Guardian reports.

Adler, who left OpenAI in November, said in a series of posts on X that he'd had a "wild ride" at the US company and would miss "many parts of it".However, he said the technology was developing so quickly it raised doubts about the future of humanity."I'm pretty terrified by the pace of AI development these days," he said. "When I think about where I'll raise a future family, or how much to save for retirement, I can't help but

wonder: will humanity even make it to that point?Adler's fears have been echoed by some of the world's leading AI researchers, Fortune pointed out.

Stuart Russell, professor of computer science at the University of California, Berkeley, told the Financial Times that the "AGI race is a race towards the edge of a cliff."

"Even the CEOs who are engaging in the race have stated that whoever wins has a significant probability of causing human extinction in the process, because we have no idea how to control systems more intelligent than ourselves," he said.

Adler's and Russell's comments come amid increased attention on a global AI race between the US and China. The news that Chinese company DeepSeek had potentially built an equal or better AI model than leading US labs at a fraction of the cost spooked US investors on Monday and sparked a reaction from leading tech figures, including OpenAI CEO Sam Altman.

Wall Street tech stocks recover a day after DeepSeek selloff hit Nvidia

Nvidia, which lost 17% in Monday's session, the biggest one-day loss in market history, rose 8.9% on Tuesday as investors looked for buying opportunities.

New Delhi Technology stocks on Wall Street saw some recovery on Tuesday, after the losses suffered the previous day when Nvidia saw its market value fall by $593 billion.The massive selloff in Nvidia's stock was triggered by the rise of Chinese AI startup DeepSeek, which introduced a low-cost AI assistant that investors feared could disrupt the dominance of US companies in the artificial intelligence sector.Nvidia, which lost 17% in Monday's session, the biggest one-day loss in market history, rose 8.9% on Tuesday as investors looked for buying opportunities. Other tech stocks, including semiconductor, power, and infrastructure companies linked to AI, also regained ground after collectively losing over $1 trillion in market value a day earlier.

US TECH STOCKS GAIN GROUND

Much of Tuesday's gains in the tech sector were driven by major companies like Apple and Microsoft. Apple rose 3.7%, making it the second-biggest boost for the Nasdaq after Nvidia.Microsoft gained 2.9%, recovering from losses earlier in the week. Meta Platforms, the parent company of Facebook, added 2.2%, marking its seventh straight day of gains despite the AI-driven market turmoil.The overall technology sector rose 3.6% on Tuesday after falling 5.6% the day before.

The Philadelphia semiconductor index, which tracks major chip companies, gained 1.1% after suffering a 9.2% drop on Monday, the steepest one-day percentage fall since March 2020.

Investors began to question whether DeepSeek's AI model could truly live up to its claims of lower costs and efficiency.

"Yesterday was an initial reaction. Today investors are asking if anybody did any sort of homework and made sure DeepSeek is exactly what they say it is. Can we have more proof that they really built it for so much less?" said Jay Kinahan, president of brokerage firm Tastytrade, in an interview with Reuters.Nvidia closed Tuesday at $128.99 per share, still lower

than its Friday close of $142.62. Other major tech stocks also showed signs of recovery.Oracle, which had dropped 13.8% on Monday, ended the session up 3.6%. Marvell Technology, which had fallen 19%, rose 3.5%, while chipmaker Broadcom recovered 2.6% after Monday's 17.4% drop.EXPERTS BULLISH ON AI STOCKSDespite Monday's selloff, some investors see the rise of DeepSeek as a positive sign for the AI industry.Steven Cohen, founder of Point72 Asset Management, said at a conference in Miami on Tuesday that DeepSeek's breakthrough is "actually bullish because it advances the move to artificial intelligence," as reported by Reuters.Traders also showed renewed interest in Nvidia. While the stock suffered a historic drop, options traders quickly returned, betting on a recovery.Cody Acree, a semiconductor industry analyst at Benchmark Company, told Reuters that the emergence of cheaper AI models would not reduce the need for high-performance chips. While companies like DeepSeek may develop cost-effective AI software, they still require powerful hardware to train and operate their models.OpenAI CEO Sam Altman called DeepSeek's model "impressive" but added that competition is a good thing."We will obviously deliver much better models, and also it's legit invigorating to have a new competitor!" Altman said in a social media post.US President Donald Trump commented on DeepSeek, calling it "a wake-up call for our industries."

Delhi, Haryana war over water gets political colours ahead of elections

▸Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini dismissed these allegations, demanding an apology from Kejriwal and threatening a defamation suit.

NEW DELHI. The battle for water between Delhi and Haryana has resurfaced amid the fervent campaign for the February 5 Assembly elections in Delhi.

AAP chief Arvind Kejriwal has accused the BJP-led Haryana government of contaminating the river, labelling it as an attack on Delhi's drinking water.

Incumbent Chief Minister Atishi went further, accusing Haryana of "water terrorism."In a letter to the EC, she cited a Delhi Jal Board report, which flagged dangerous ammonia levels in Yamuna water from Haryana, rising to seven parts per million – 700% above treatable limits – due to untreated sewage and industrial waste.Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini dismissed these allegations, demanding an apology from Kejriwal and threatening a defamation suit. Saini countered that Haryana reveres the Yamuna as a sacred river, asserting that the accusations tarnished its honour.

This clash is the latest episode in a decades-long feud between the two states over the Yamuna, which has been fought in courts and political arenas since 1995, shortly after Delhi got its

Legislative Assembly.

Legal battles began in 1995 when the Supreme Court, responding to Delhi's plea for a steady water supply, ordered Haryana to ensure adequate flow. This decision was based on a 1994 memorandum of understanding (MoU) signed by Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Himachal Pradesh on Yamuna water allocation.However, tensions escalated quickly, with contempt petitions filed against Haryana for alleged violations of the top court order. In 1996, the court ruled that Delhi's water supply must remain uninterrupted, irrespective of the MoU.

Despite the directives, disputes persisted. In 2018, the DJB alleged Haryana was supplying only a third of Delhi's rightful share, prompting the apex court to urge dialogue between the states. Later that year, Haryana offered to release additional water if Delhi withdrew pending legal cases, but the issue remained unresolved.

Conflict erupted again in 2021, with DJB accusing Haryana of ignoring the 1996 Supreme Court ruling by allowing water levels in Delhi's reservoirs to drop. Haryana, in turn, blamed Delhi's internal mismanagement. That same year, AAP leaders accused Haryana and neighbouring states of polluting the river, depriving Delhi of clean water.In 2023, the rivalry took a different turn when a severe flood hit Delhi. AAP accused Haryana of deliberately releasing water from the Hathnikund Barrage to inundate the capital. This barrage, central to the 1994 MoU, regulates Yamuna water allocation among states.

How many cases filed over triple talaq? Supreme Court seeks data from Centre

New Delhi. The Supreme Court, on Wednesday, directed the Central government to provide data about the criminal cases registered under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 for the pronouncement of triple talaq. The court was hearing a batch of petitions filed by Muslim organisations challenging the constitutionality of the 2019 Act.A Bench of Chief Justice of India Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar, while hearing 12 petitions challenging the constitutionality of the 1991 Muslim Women (Protection of Rights in Marriage) Act, also asked about the pending triple talaq cases and any challenges pending before the High Courts against the enactment.

"Parties to file written submissions on both sides. Check up and give us data on the number of FIRs registered," the Supreme Court ordered.The petitioners argued that the law has introduced penal legislation specific to a class of persons based on religious identity. It is causative of grave public mischief, which, if unchecked, may lead to polarisation and disharmony in society.

They further contended that since the Supreme Court had already declared the practice of instant triple talaq as unconstitutional in the Shayara Bano case, the law serves no purpose.It has been argued that the intent behind the Act is not the abolition of triple talaq but punishment of Muslim husbands.The Court also remarked that the petitioners were only challenging the criminalisation of the practice and not defending the practice itself.

"I am sure none of the lawyers here are saying that the practice is correct, but what they are saying is that whether it can be criminalised when the practice is banned and no divorce can take place by uttering talaq three times at once," CJI Khanna remarked.

When the Court was adjourning the matter, SG Mehta chose to refer to an Urdu couplet by Pakistani poet Parveen Shakir on divorce,"Talaq de to rahe ho Äähurur-o-shroor ke saathmeri jawani bhi lauta do mere mehr ke saath"

The bench fixed the petitions for final hearing in the week commencing March 17.Notably, the Supreme Court on August 22, 2017 had criminalised the 1,400-year-old practice of 'triple talaq' among Muslims. The court set the practice aside on several grounds, including that it was against the basic tenets of Quran and violated the Islamic law Shariat.

MEA summons Sri Lankan envoy, 'strongly' protests navy's firing on Indian fishermen

NEW DELHI. A firing incident by the Sri Lankan Navy near Delft Island early Tuesday left five Indian fishermen injured, including two with serious injuries, prompting a strong diplomatic response from India.Priyanga Wickramasinghe, Acting High Commissioner of Sri Lanka in New Delhi was summoned to the External Affairs Ministry and a strong protest was lodged over the incident. The Sri Lankan diplomat was told that use of force is not "acceptable" under any circumstances whatsoever.

"Our High Commission in Colombo has also raised the matter with the Ministry of Foreign Affairs of the Sri Lankan government," External Affairs Ministry said in a statement."An incident of firing by the Sri Lankan Navy during the apprehension of 13 Indian fishermen in the proximity of Delft Island was reported in the early hours of this morning," the MEA said.

Out of the 13 fishermen who were on board the fishing vessel, two have suffered serious injuries and are currently receiving treatment at the Jaffna Teaching Hospital."Three other fishermen received minor injuries and have been treated for the same. Indian Consulate Officials in Jaffna have visited the injured fishermen at the hospital to seek their welfare and are extending all possible assistance to the fishermen and their families," the statement said.The Government of India has stressed the importance of addressing issues related to fishermen in a humane and humanitarian way, with consideration for their livelihoods. The use of force is unacceptable, and existing agreements between the two governments should be strictly followed.

Balance privacy with need for DNA test in paternity dispute cases: Supreme Court

NEW DELHI. Courts must be mindful of the collateral infringement of privacy of the child and the parents while permitting an enquiry into somebody's paternity by a DNA test, the Supreme Court said on Tuesday.A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan, said that forcefully undergoing a DNA test would subject an individual's private life to scrutiny from the outside world. The ruling brought the curtain down on a two-decade-old dispute over paternity by a person from Kerala."That scrutiny, particularly when concerning matters of infidelity, can be harsh and can eviscerate a person's reputation and standing in society. It can irreversibly affect a person's social and professional life, along with his mental health," the bench said.

Laying down the procedure of when a court can order a DNA test to ascertain an individual's paternity, the top court said that courts should assess the eminent need for a DNA test and there should be a balancing of interests.

"On one hand, courts must protect the parties' rights to privacy and dignity by evaluating whether the social stigma from one of them being declared 'illegitimate' would cause them disproportionate harm. On the other hand, courts must assess the child's legitimate interest in knowing his biological father and whether there is an eminent need for a DNA test," the bench said.

The bench pointed out that the effects of social stigma about an illegitimate child making their way into the lives of parents and there could be scrutiny owing to alleged infidelity.

Casting aspersions on a married woman's fidelity would ruin her status, dignity and reputation, and she would be castigated in society, it added."First and foremost, the courts must, therefore, consider the existing evidence to assess the presumption of legitimacy. If that evidence is insufficient to come to a finding, only then should the court consider ordering a DNA test," the court said.Once the insufficiency of evidence is established, the court must consider whether ordering a DNA test is in the best interests of the parties involved and must ensure that it does not cause undue harm to the parties. There are thus two blockades to ordering a DNA test: (i) insufficiency of evidence; and (ii) a positive finding regarding the balance of interests," it added.

'Genocide remarks can endanger national security': Lieutenant Governor VK Saxena writes to CM Atishi

NEW DELHI. Lieutenant Governor VK Saxena wrote to Chief Minister Atishi on Tuesday, alleging that AAP supremo Arvind Kejriwal's allegations that "poison" is being mixed into Yamuna water and there was an "attempt of genocide" in the capital are highly objectionable, and amount to endangering national security.

Citing media reports, Saxena said the former Delhi chief minister's allegations against the BJP-led Haryana government of poisoning the Yamuna river and attempting a "genocide" in Delhi are "highly objectionable, unfortunate and undesirable"."Making false, misleading, non-factual accusations of poisoning and genocide over a sensitive issue like drinking water and attempting to incite the public against another state government is not only a threat to the states involved but also to national peace and security," he said in the letter to the chief minister.

The L-G also pointed out that instead of condemning Kejriwal's statements, Atishi strengthened the "confusion and fear" among people by writing a letter to the Election Commission (EC) over the matter.

Saxena said he expects the Chief Minister to rise above "narrow interests" and refrain from making "misleading, dangerous, and baseless statements, and advise the AAP convenor to do the same for sake of public welfare."Delhi's water crisis took a sharp political turn on Monday, with thw AAP supremo accusing Haryana government of "biological warfare". "Poison is being mixed into the Yamuna to make its water untreatable. If people in Delhi consume this water, many will die," he wrote.

Muslim woman seeks succession law

NEW DELHI. The Supreme Court on Tuesday sought the Centre's stand after hearing a Muslim woman's plea seeking to be governed by the Indian succession law.A woman from Alappuzha in Kerala, Safiya P M, had moved the SC stating that she is a non-believer Muslim and hence should be governed by the Indian Succession Act 1925 concerning inheritance instead of the Muslim Personal Law (Sharia Law).

After hearing Safiya's plea, the apex court sought a response from the central government within four weeks.A three-judge bench led by Chief Justice Sanjiv Khanna and comprising Justices Sanjay Kumar and KV Viswanathan said, "We will hear this plea after we receive the reply." The matter was posted for May first week.

Safiya, the general secretary of "Ex-Muslims of Kerala", said that as per Shariat law, a Muslim person cannot bequeath more than 1/3rd of his/her properties by way of will. "Her father cannot bequeath more than 1/3rd of the property to her, and the remaining 2/3rd will go to her brother, who was suffering from Down's syndrome," the plea stated.

The petitioner said she has a daughter, and after her death, the entire property will not go to her daughter as her father's brothers will also get a claim.

Safiya said that she has not officially left Islam. She is a non-believer and wants the enforcement of her fundamental right to religion under Article 25 of the Indian constitution.Safiya has sought a declaration from the apex court that the persons who do not want to be governed by the Muslim Personal Law must be allowed to be governed by the secular law of the country i.e. the Indian Succession Act, 1925, both in the case of intestate and testamentary succession.

Solicitor General Tushar Mehta, a senior lawyer representing the Centre, said the plea raised an interesting question. He said the Centre will file its reply as per the SC's order.

Mehta further said that Safia has only one daughter and wanted to bequeath the entire property to her, but Sharia law allows bequething of only 50%. "She wants the benefit of the Indian Succession Act, the secular law," he said.Last year, the top court notified the Centre and Kerala on the petition. As per Sharia law, the person who leaves her faith in Islam will be ousted from her community, and thereafter, she is not entitled to any inheritance right in her parental property, the petition said.

Relief to CM Naidu as SC rejects plea to transfer CID cases against him to CBI

NEW DELHI. In a major relief to Chief Minister N Chandrababu Naidu, the Supreme Court on Tuesday rejected a plea seeking the transfer of CID (Crime Investigation Department) cases against him to the CBI (Central Bureau of Investigation), stating that the petition lacked "merit."A two-judge bench, comprising

Justices Bela M Trivedi and Prasanna B Varale, delivered the order after hearing a plea filed by one Balaiah B. "There is no merit in the petition. We are sorry. We reject it," the Supreme Court stated in its order.

In his petition, Balaiah had sought the transfer of seven cases against the TDP supremo from the CID to the CBI, citing a conflict of interest and alleged compromised administrative control.

The petitioner claimed that the current State administration, led by the TDP, had been using its influence to hinder investigations into cases involving allegations of corruption, money laundering, and criminal misappropriation. The plea also pointed out that the CID had already filed charge sheets in five of the cases, while investigations in two others were still pending.

What led to Maha Kumbh stampede? Congress blames VIP culture; CM cites overcrowding

New Delhi. A stampede broke out on Wednesday as millions of people flocked to the ghats to take a holy dip in Prayagraj where the grand Maha Kumbh mela is taking place. Ten people lost their lives while many others were seriously injured in the incident that gave Opposition an opportunity to attack the state government. Congress blamed 'VIP culture' for the unfortunate incident, targeting the Yogi Adityanath-led administration.Till 8.30am on Wednesday, around 3.5 crore pilgrims had taken holy dip at Maha Kumbh mela, CM Yogi said, emphasising the enormous crowd the event is attracting. However, he assured that he is continuously monitoring the situation along with senior officers.

CONGRESS BLAMES VIP CULTURE

Leader of the Opposition Rahul Gandhi said the news from Prayaraj is heart-rending and alleged poor management by the state government. "Poor management and prioritising VIP movement over ordinary pilgrims is responsible for this tragic incident," he said, adding that the government should make proper arrangements to prevent a recurrence of such an incident. "VIP culture should be checked and better arrangements must be made for the pilgrims," Gandhi said.

Congress president Mallikarjun Kharge has said in a post on X, "Half-baked preparations, VIP movement and a focus on self-publicity instead of management is responsible for this. Such preparations despite spending thousands of crores in condemnable."

"Facilities for lodging pilgrims and first-aid must be expanded and VIP movement checked. Our saints want the same," he added.The Congress leaders' jabs over VIP culture come after high-profile BJP leaders, including Union Home Minister Amit Shah and Chief Minister Yogi Adityanath, visiting the Mahakumbh to take the holy dip.

Coldplay frontman Chris Martin also arrived at Maha Kumbh Mela with his girlfriend Dakota Johnson.

WHAT CM YOGI SAID

"Around 8-10 crore devotees are present in Prayagraj today. There is continuous pressure due to the movement of devotees towards the Sangam Nose. A few devotees have suffered serious injuries when they tried to cross barricading on Akhara Marg. The injured been shifted to hospitals for medical treatment."The CM said the Prime Minister Narendra Modi has called four times so far to stake stock of the situation. He further assured that the situation is under control and.

"The situation in Prayagraj is under control but the crowd size remains massive...There are large crowds at Sangam Nose, Nag Vasuki Marg and Sangam Marg," the CM said.He also appealed to devotees to not pay attention to any rumour and take holy dip at the ghats nearest to them.

WHAT EXACTLY HAPPENED

The stampede broke out at around 2 am when a sea of devotees converged at the Sangam to take a holy dip on the occasion of Mauni Amavasya. The Triveni Sangam in Prayagraj is the sacred meeting point of the Ganga, Yamuna, and mythical Saraswati rivers. Pilgrims believe bathing here cleanses sins and ends the cycle of rebirth. As a result, the Sangam Nose became the most visited spot during the Maha Kumbh.

NEWS BOX

Mayors of Hiroshima, Nagasaki invite Trump for 80th anniversary of World War II atomic bombings

World The mayors of Hiroshima and Nagasaki have invited US President Donald Trump to visit this year for the 80th anniversary of the World War II atomic bombings, officials said Wednesday.In a joint letter to Trump, the mayors urge him to come and "listen to the testimonies of the hibakusha (bomb survivors) in person, take to heart their fervent wish for peace, and deepen your understanding of the inhumanity of nuclear weapons"."It is our sincere hope that you will break away from the notion of nuclear reliance and take strong leadership in the abolition of nuclear weapons and the realization of lasting world peace," said the January 28 letter shared with AFP on Wednesday.The United States dropped an atomic bomb on each Japanese city on August 6 and 9, 1945 -- the only times nuclear weapons have been used in warfare. Days later Japan surrendered.Around 140,000 people died in Hiroshima and some 74,000 others in Nagasaki including many who survived the explosions but died later from radiation exposure.

Washington has never apologised for the bombings.

US ambassador John Roos in 2010 became the first US representative to attend the annual Hiroshima commemoration and went to the Nagasaki event two years later.Barack Obama became the first sitting US president to come to Hiroshima in 2016, followed by Joe Biden in 2023.Trump did not make the trip during his first term, despite the two mayors inviting him according to Japanese media.

Last year, Nagasaki's mayor Shiro Suzuki sparked a furore by not inviting Israel's ambassador to the ceremony.Suzuki insisted the decision was "not political" but to avoid possible protests related to the Gaza conflict.The ambassadors of the US, Israel, Britain and others snubbed the ceremony in protest and attended a smaller memorial event in Tokyo instead.Last year's Nobel Peace Prize was awarded to Nihon Hidankyo, a grassroots movement of Hiroshima and Nagasaki survivors pushing for a nuclear weapons ban.

No food, nothing': Famine grips Sudan

World In the span of just two months, the Sudanese mother watched helplessly as severe malnutrition killed her 10-year-old daughter, Rania, and her eight-month-old son, Montasir, in the famine-stricken Zamzam displacement camp."I could only hold them as they faded away," Ibrahim, 40, told AFP via video call, sitting outside her straw-and-plastic shelter near North Darfur state's besieged capital El-Fasher.

Rania was the first to succumb. In El-Fasher's only functioning hospital, understaffed and unequipped, she died in November just three days after being admitted with acute diarrhoea.Her baby boy Montasir followed weeks later, his tiny body bloated from severe malnutrition.El-Fasher, under paramilitary siege since May, is only one grim battlefield in the 21-month war between the Sudanese army and the Rapid Support Forces (RSF).

In July, a UN-backed review declared famine in Zamzam, a decades-old displacement camp home to between 500,000 and a million people.By December, it had spread to two more camps in the area, Abu Shouk and Al-Salam, as well as parts of the Nuba Mountains in southern Sudan, the Integrated Food Security Phase Classification determined.

The Sudanese government, aligned with the army, has denied reports of famine, even as millions across the country suffer on the brink of starvation.Now, Ibrahim fears for her four-year-old daughter, Rashida, who battles severe anaemia with no access to medical care."I am terrified I will lose her too," she said."We're abandoned. There is no food, no medicine, nothing."At Salam 56, one of Zamzam's 48 overcrowded shelters, exhaustion was etched onto mothers' faces as they cradled their children, too weak to stand.Multiple families gathered around bowls with a few scraps of peanut residue traditionally used as animal feed.

Sad to watch new govt dismantling all freedoms we've been fighting for: Madonna

LOS ANGELES. Pop icon Madonna has criticised the newly elected Donald Trump administration for its decision to remove protections for transgender people and end diversity, equity and inclusion efforts, urging citizens to keep fighting for their rights.

It's the latest push by Trump to reverse policies set by former president Joe Biden's government to protect transgender people and their care.On Monday, Trump directed the Pentagon to conduct a review that is likely to lead to them being barred from military service.Madonna, a longtime advocate for the LGBTQ community, expressed her disappointment in an X post on Tuesday.

"It's so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. Don't give up the Fight! (sic)" she wrote, adding the LGBTQ pride flag and broken red heart emojis.Earlier, singer-actor Selena Gomez, whose father is of Mexican descent, got emotional over the Trump administration's stand over the deportation of undocumented immigrants on social media in a now-deleted Instagram video.

Study says climate change made conditions that fed California wildfires more likely, more intense

WASHINGTON. Human-caused climate change increased the likelihood and intensity of the hot, dry and windy conditions that fanned the flames of the recent devastating Southern California wildfires, a scientific study found.

But the myriad of causes that go into the still smoldering fires are complex, so the level of global warming's fingerprints on weeks of burning appears relatively small compared to previous studies of killer heat waves, floods and droughts by the international team at World Weather Attribution. Tuesday's report, too rapid for peer-review yet, found global warming boosted the likelihood of high fire weather conditions in this month's fires by 35% and its intensity by 6%.Once-in-a-decade super strong Santa Ana winds, a dry autumn that followed two very wet years that caused rapid growth in flammable chapparal and grass, hot weather, dry air and vulnerable houses in fire-prone areas all were factors in the fast-moving fires that destroyed thousands of homes and killed at least 29 people, study authors said. But the climate attribution team was only able to quantify issues that dealt with the fire weather index, which are the meteorological conditions that add up to fire danger.The fire weather index — which includes measurements of past rainfall, humidity and wind speed — is where the team looked and found markers of climate change that they could quantify.

The team used observations of past weather and computer simulations that compared what happened this month to a what-if world without the 1.3 degrees Celsius (2.3 degrees Celsius) of human-caused climate change that Earth has had since industrial times. That allowed them to come up with a calculation for warming's contribution to the disaster. It's a method that the National Academy of Sciences says is valid. Even though these rapid studies aren't yet peer-reviewed, nearly all of them are published later in peer-reviewed journals without significant changes, said World Weather Attribution co-lead scientist Friederike Otto."The number (35%) doesn't sound like much" because unlike dozens of its past studies, the team looked at a small area and a complex meteorological measurement in the fire weather index that

would generally mean there would be large uncertainties, said Otto, a climate scientist at Imperial College London. But in this case the climate change fingerprint is big enough that it stands out, she said.Those conditions are part of what makes California attractive to 25 million residents, said study co-author John Abatzoglou, a climate and fire scientist at the University of California Merced.Southern California has "some of the best climate, best weather on the planet — except when you get a combination of conditions that occurred here," Abatzoglou said. "You get the trifecta of dry windy and warm conditions. Those three things, in combination with dry fuels and ignitions, are the perfect recipe for fire disasters."Abatzoglou said it's like a bunch of switches — dryness, fuels, high temperatures, wind and ignition — that all need to be turned on "for conditions to really take off." Think of it as switches for a light bulb to illuminate — "and so you can think about the artificial warming due to human-caused climate change making the light brighter," added co-author Park Williams, a UCLA fire and climate scientist.The study also found California's dry season has increased by 23 days and the lack of rain in October, November and December was more than twice as likely now than in pre-industrial times, but because of limitations on the data, researchers couldn't statistically pinpoint these to both climate change and the specific fires this month, Otto said. But she said "the rains are decreasing — that is because of human-induced climate change.

Who can share seedsAs climate change and counterfeits hurt Kenyan farmers, it's a growing question

KIKUYU. Tucked away in a lush, forested area of central Kenya's Kikuyu town, the National Seed Bank stands as a crucial safeguard for the future of the country's agriculture. Inside two chilly rooms of a government building, more than 50,000 seed varieties are cataloged and stored.The bank was established in 1988 after the realization that some traditional varieties of seeds were being lost, an occurrence that is becoming more common with climate change. It aims to conserve seeds for research and reintroduction to farms.

"We realize that some of the traditional varieties that we had abandoned then are actually more resilient to climate change, so when you introduce them especially in marginal areas, those varieties outperform the improved varieties," said the director of the Genetic Resources Research Institute that operates the bank, Desterio Nyamongo, referring to hybrid seeds that must be bought every planting season.He said the some of bank's seeds also were found to be more resistant to diseases and pests and were high-yielding.This gives hope to a country that relies heavily on rain-fed

agriculture instead of irrigation, leaving it more vulnerable to climate shocks like drought. The sector contributes a third of Kenya's GDP.

Kenya is not alone facing food security pressures. According to a U.N Food and Agriculture and Organization report in 2023, over a billion people across the African continent are unable to afford healthy diets, and the number of hungry people is increasing.

But in Kenya, another complication has emerged. Farmers in recent months suffered losses in the millions of shillings (tens of thousands of dollars) after planting counterfeit seeds bought from private sellers.Kenyan officials have acknowledged that the seed sector is critical.During the country's first international seed quality conference in August, the agriculture ministry's permanent secretary, Paul Rono, said Africa has limited capacity to produce high-quality certified seeds that are subjected to quality standards.

The head of the Eastern Africa Farmers Federation, Stephen Muchiri, said the vigor of crops in Kenya has become low, and he believes that the main reason is a flawed seed breeding and propagation program.But some farmers say efforts to improve the seed system in Kenya have been limited by a 2012 law banning seed sharing, which is what millions of farmers did every planting season to cut their production cost.The government has said the law is meant to prevent the circulation of uncertified seeds and protects farmers, but it faces a court challenge from more than a dozen farmers across Kenya who say it's expensive having to buy new seeds every planting season. The next hearing in the case is in March.

Francis Ngiri is one of the farmers who filed the case. He runs an indigenous seed bank for the local community on his five-acre farm in the semi-arid Gilgil area located 120 kilometers (74 miles) from the capital, Nairobi.

North Korean leader Kim inspects nuclear facility as Pyongyang pressures Trump administration

SEOUL, South Korea. North Korean leader Kim Jong Un inspected a facility that produces nuclear material and called for bolstering the country's nuclear fighting capability, state media reported Wednesday, as the North looks to increase pressure on the United States following the inauguration of President Donald Trump.Kim's visit suggests a continued emphasis on an expansion of North Korea's nuclear arsenal, though Trump has said he's willing to talk to Kim again to revive diplomacy. Many analysts view North Korean weapons moves as part of a strategy to win sanctions relief and political concessions from the United States.

The official Korean Central News Agency reported that Kim visited the nuclear-material production base and the Nuclear Weapons Institute. It didn't say where those facilities are located, but North Korean photos of Kim's visit indicated that he likely visited a uranium-enrichment facility that he went to last September. That visit was North Korea's first disclosure of a uranium-enrichment facility since it showed one to visiting American scholars in 2010.During the latest visit, Kim said North Korea reported "amazing" results in its production of nuclear material last year and underlined the need to exceed this year's production goal to

strengthen "the nuclear shield of the country," according to KCNA.Kim said that further boosting the country's nuclear counteraction posture is "our invariable noble task" to cope with intensifying challenges posed by "hostile forces," an apparent reference to the US and South Korea.The start of Trump's second term raises prospects for the resumption of diplomacy between the United States and North Korea, as Trump met Kim three times during his first term. The Trump-Kim diplomacy in 2018-19 fell apart due to wrangling over US-led economic sanctions on North Korea, and Kim has since significantly dialed up weapons testing activities.During a Fox News interview broadcast Thursday, Trump called Kim "a smart guy" and "not a religious zealot." Asked whether he will reach out to Kim again, Trump replied, "I will, yeah."North Korea hasn't yet directly responded to Trump's overture as it continues its belligerent rhetoric against the US along with weapons testing activities.

Discovery of brutal mass graves in Syria reveals Assad's legacy of horror

DAMASCUS, Syria. The charred remains of at least 26 victims of the Bashar Assad government were located Tuesday by Syrian civil defense workers in two separate basements in rural Damascus.The discovery adds to the growing tally of mass graves unearthed since the fall of the Assad government in December. The remains, which are believed to include men, women and children, showed evidence of gunshot wounds and burning.

Members of Syria's White Helmets, a volunteer civil defense group, exhumed the fragmented, weathered skeletal remains from the basement of two properties in the town of Sbeneh, southwest of the capital. Wearing hazmat suits, they carefully logged and coded each set of remains before placing them into body bags, which were then loaded onto trucks for transport.Since Nov. 28, the White Helmets have uncovered "more than 780 bodies, most of unknown identity," Abed al-Rahman Mawwas, a member of the rescue service, told The Associated Press. He said many were found in shallow graves uncovered by locals or dug up by animals. The bodies are transferred to forensics doctors to determine their identities, time of death and cause of death, as well as to match them with possible family members.

"Of course, this takes years of work," he said.Mohammad al-Herafe, a resident of one of the buildings where remains were uncovered, said the stench of decomposing bodies was overwhelming when his family returned to Sbeneh in 2016 after fleeing because of fighting in the area during the country's uprising-turned-civil war that began in 2011.He said they found the bodies in the basement but chose not to report it out of fear of government reprisals. "We could not tell the regime about it because we know that the regime did this."The Assad government, which ruled Syria for over two decades, employed airstrikes on civilian areas, torture, executions and mass imprisonment, to maintain control over Syria and suppress opposition groups during the country's 13-year civil war.Ammar al-Salmo, another Civil Defense member dispatched to the second basement site, said further investigation is needed to identify the victims.We need testimonies from residents and others who might know who stayed behind when the fighting intensified in 2013," he told the AP.

White House opens doors to 'new media', allocates seats in press briefing room

WASHINGTON. The Trump Administration has announced that it will allocate seats in the White House press briefing room to representatives from "new media" outlets, including podcasters, social media influencers, and content creators.

This move, spearheaded by Press Secretary Karoline Leavitt, aims to provide representation to groups that have not previously had a presence in the briefing room."Millions of Americans, particularly young people, have shifted away from traditional television and newspapers to consume news through podcasts, blogs, social media, and other independent platforms," Leavitt said on Tuesday during her first daily press briefing."It is crucial for our team to share President Trump's message widely and adapt the White House to the evolving media landscape of 2025," Leavitt said.At just 27 years old, Leavitt is the youngest White House press secretary in history.She invited independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for White House press credentials through the newly launched website, whitehouse.gov/newmedia.She also revealed that a front-row seat in the briefing room, traditionally reserved for the press secretary's staff, will now be designated the "New Media Seat."Applications will be reviewed by Leavitt's team, and credentials will be granted to those who meet the criteria and pass the US Secret Service's security requirements.During her first briefing, Leavitt fielded questions from new media representatives, including outlets that rank among the most-viewed news websites in the country but have never had a seat in the briefing room.When asked about the initiative, Leavitt reiterated the administration's commitment to upholding the First Amendment."It's a fact that Americans, especially young people, are consuming news from a variety of platforms. As the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take

great pride in opening this room to new media voices to ensure the president's message reaches as many Americans as possible," she said.

She added, "We will ensure that respected outlets like Axios and Breitbart have a permanent seat in this room every day.

We also encourage anyone in the country whether you're a TikTok creator, blogger, podcaster, or any other type of content producerto apply for press credentials if you are producing legitimate news content, regardless of the platform."

The move marks a significant shift in the White House's approach to media engagement, reflecting the changing ways Americans access and consume news in the digital age.Leavitt also emphasised the administration's commitment to the First Amendment, announcing plans to reinstate press passes for 440 journalists whose credentials were revoked under the previous administration.

"This White House strongly believes in the First Amendment, which is why we are working diligently to restore press passes to journalists who were wrongly denied access.Additionally, we are opening this briefing room to new media voices that produce news-related content but currently lack representation here," she explained.

NEWS BOX

Alyssa Healy declares herself fit for Women's Ashes Day-Night Test: Ready to go

New Delhi Skipper Alyssa Healy said that she was "good to go" for the Women's Ashes Test against Heather Knight's England at the iconic Melbourne Cricket Ground. The 34-year-old Healy played in the ODI leg of the Ashes, but missed the three-match T20I series due to an injury to her right foot.Healy, who has played nine Tests since her debut in 2011, declared herself fit before the game, but said that Australia haven't finalised their playing XI for the Day-Night Test. Due to a stress reaction on her foot, Healy had to wear a moon boot throughout the last week.

"I'm good to go. We'll make a final decision on what the XI looks like over the next little period ... but I feel like I'm ready to go, so we'll wait and see what happens," Healy said in the pre-match press conference."The final XI hasn't quite been decided upon just yet, but I'm standing here in front of you without a moon boot, saying I'm ready to go," Healy said.

'Have done everything possible'

Healy has had her fair share of troubles with a foot injury after she missed a few games in the Women's T20 World Cup where Australia crashed out in the semi-final. She also missed the WBBL due to a left knee injury. Before the upcoming Test, Healy took laps of the ground and also participated in fielding drills."The medical staff have been really supportive of (giving me) the opportunity to even push to play in this Test match. We've done everything we possibly can to get myself in a position to put my hand up and say, 'I'm ready to go'," Healy added.

All-rounder Ash Gardner has also been cleared to play after she did not play in the T20Is due to a calf injury. Fast bowler Megan Schutt, however, will miss out after national selector Shawn Flegler confirmed earlier that Australia would persist with the duo of Kim Garth and Darcie Brown.

Neymar returns to Brazilian club Santos after termination of contract in Saudi Arabia

Neymar won six titles with his boyhood club Santos, including a Copa Libertadores trophy in 2011.

RIO DE JANEIRO. Neymar has agreed to return to Santos nearly 12 years after he left the Brazilian team, club president Marcelo Teixeira said Tuesday.The Brazil striker confirmed earlier that his contract with Saudi Arabian club Al-Hilal had been terminated by mutual consent. He had an injury-marred spell at Al-Hilal, where he played only seven matches and scored once.Neymar won six titles with his boyhood club Santos, including a Copa Libertadores trophy in 2011. Santos is a beachfront city outside São Paulo."It is the time (to come back), Neymar. It is time for you to come back to your people. To our home, to the club in our hearts," Teixeira said in his social media channels. "Welcome, Santos' boy Ney! A boy of Vila (Belmiro, Santos' stadium). Come back to be happy again with the white and black shirt. The Santos nation awaits you with open arms."Neymar, once hailed as one of the world's best players, spent much of his time in Saudi Arabia on the sidelines due to an ACL injury he picked playing for Brazil in October 2023.São Paulo media reported that the former Barcelona and Paris Saint-Germain star is expected to return to Brazil this week and reintroduce himself to Santos fans within days.Neymar became the most expensive player in soccer history when he transferred from Barcelona to PSG for 222 million euros (then $262 million) in 2017.

"(My father) must be taking bicycle kicks in heaven after finding out that our boy is coming back home," Nascimento said on Instagram. Pelé died in December 2022.

A video published by Al-Hilal on Tuesday evening shows Neymar giving a farewell speech."Today I am very happy to be able to go, return home. To my country," Neymar told his former teammates, without mentioning Santos. "It was a pleasure for me to play for this club. It was a short time, things were not as I expected. I could not

help you on the pitch as I wanted."Santos was relegated to Brazil's secnd division in 2023 and was promoted again in the latest season.Neymar's most recent match was played in November. Al-Hilal coach Jorge Jesus had repeatedly cast doubts about the striker's form to play.Neymar left the Saudi Arabian league after playing just seven games in 17 months following his big-money move to the oil-rich kingdom.Al-Hilal said Monday it reached an agreement with Neymar to terminate his contract by mutual consent.Neymar's spokeswoman, Day Franco, told The Associated Press the player had no immediate comment.However, Neymar responded with a heart gif to a post of Kely Nascimento, one of the daughters of three-time World Cup winner Pelé, celebrating his return to Santos."I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together," Neymar said in a message on social media. "To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences. I now know the real Saudi and have friends for life."Despite Neymar's injury, Al-Hilal still managed to win last season's Saudi league. The Brazilian's contract was due to expire after this year's FIFA Club World Cup, which will be played between June 15 and July 13 in the United States. The striker joined the Saudi club from PSG in August 2023 for 90 million euros ($94 million). His salary was reportedly one of the biggest in world soccer as well.But Neymar picked up his ACL injury playing for Brazil only months after he joined Al-Hilal.Neymar returned in October but said in different interviews there were doubts over whether he would stay for the rest of the season.Santos fans have already been expecting Neymar's return. Since last week, they have posted a video of a man with the voice of legendary three-time World Cup winner Pelé.

Ignoring pacers, under-using Sundar: Aakash Chopra questions India's selection

New Delhi Former India cricketer Aakash Chopra has raised concerns over India's team selection in their ongoing T20I series against England, citing it as a key reason for their defeat in the third T20I in Rajkot. After winning the first two matches, India failed to seal the series, allowing England to pull one back with a win on January 28. Chopra believes India has not fully utilised its squad depth, which has contributed to the inconsistent team performance.While Abhishek Sharma and Tilak Varma guided India to victories in the first two matches with individual brilliance and Varun Chakravarthy impressed with the ball, India has lacked a well-rounded collective effort. One of Chopra's main concerns is the underutilisation of Washington Sundar, who has been in the playing XI for the last two matches but has hardly been given the ball.

IND vs ENG, 3rd T20I: Highlights"You are saying you want four spinners. Let me agree that you need four spinners, but are you bowling 16 overs of spin? You don't do that as well. You got Washington to bowl only one over. You cannot play someone for one over. It is bizarre," Chopra added.

Sundar was introduced into the lineup in the second T20I in Chennai, replacing Nitish Kumar Reddy, but bowled just one over for nine runs. The trend continued in Rajkot,

where he was again restricted to a solitary over, conceding 15 runs. Chopra questioned why India would pick a bowling all-rounder but not use him effectively in the attack.Additionally, Chopra raised concerns about India's reluctance to field a proper combination of pacers despite having Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Hardik Pandya, and Harshit Rana in the squad. He suggested that India's team selection has not been balanced, leading to avoidable weaknesses.

"I don't think we are selecting the right team. Arshdeep Singh was playing earlier and Hardik Pandya was there with him. Then Mohammed Shami played and Hardik was there with him too. It's not that this team doesn't have any other fast bowlers, but you don't want to play any fast bowler," Chopra added.Another selection decision that raised eyebrows was Dhruv Jurel's batting position. Chopra criticised the move to send the wicketkeeper-batter as low as No. 8 in the order, a concern that was also echoed by former England captain Kevin Pietersen after the Rajkot defeat.With the series now at 2-1, India must fine-tune its playing XI for the fourth T20I in Mumbai on January 31 to ensure a strong collective display rather than relying solely on individual performances.

Travis Head stars with blistering 40-ball 57 on his return as an opener vs Sri Lanka

Australia opener Travis Head was seen at his aggressive best as he scored a blistering 40-ball 57 on Day 1 of the first Test against Sri Lanka on Wednesday, January 29 at Galle International Stadium, Galle. Head was promoted to open the innings after 22 months as the team management dropped youngster Sam Konstas from the Playing XI and handed debut cap to Josh Inglis.Despite opening the innings after a long gap, Head showed no qualms whatsoever as he smashed a boundary on the very second ball of his innings as Asitha Fernando gave him a freebie on his pads. Having got off the mark with a boundary, Head quickly got into rhythm and hit two more fours in the over, giving ominous signs to the Sri Lankan bowlers.

The Australian opener was in no mood to stay quiet at the crease and continued to take on Fernando, whacking him for two boundaries in his third over. The Sri Lankan seamer managed to hit him on his pads on the last ball of the over and went up for an appeal for lbw. However, the umpire turned it due to the possibility of ball pitching outside the leg stump, since Fernando was bowling over the

wicket.AUS vs SL 1st Test Day 1 LiveHead survives as Sri Lanka opts against DRS

The Sri Lanka captain Dhananjaya de Silva also wasn't too keen to go for DRS and decided against it. Much to his dismay, the ball tracking showed that the ball was pitching in line and Head would've had to return to the pavilion, had they opted for a review. As a result, the southpaw continued his stay at the crease as Sri Lankan bowlers had nowhere to hide from his belligerent strokeplay.Head showed no mercy to the bowlers, hitting both spinners and seamers to all corners of the ground and brought up his half century off just 35 balls. He was dismissed shortly after completing his fifty while trying to smash Jayasuriya down the ground but could only find Dinesh Chandimal at long on.

Suryakumar Yadav needs to choose when to be aggressive: Michael Vaughan

NEW DELHI. Former England cricketer Michael Vaughan has advised India's T20I skipper Suryakumar Yadav to adopt a more measured approach at the crease before shifting into aggressive mode. Vaughan believes Suryakumar's tendency to attack too early has backfired, contributing to his struggles in the ongoing T20I series against England, including India's 26-run defeat in the third T20I in Rajkot on January 28.

With India now leading the five-match series 2-1, concerns over Suryakumar's form have intensified. The batter has failed to make an impact so far, registering scores of 0, 12, and 14 in the first three matches. His dismissals have largely been a result of mistimed attacking strokes, either edging the ball behind or mis-hitting it into the air. Speaking to Cricbuzz, Vaughan emphasised that while India prioritises maximising their powerplay runs, Suryakumar must structure his innings better to fully contribute to the team."It's a few times on the trot when he's been getting out to quite soft dismissals. When

you say be aggressive all the time, it's choosing the right ball to be aggressive to. Clearly you can't hit every single ball to the boundary and some of these players in this era, they've got so much skill and talent that they think they can. It's just not possible," Vuaghan said."For India to come back, and I'm sure they will, they're not going to play any worse, I can't imagine in a few days time, but it will need maybe Sky (Suryakumar Yadav) just saying, 'okay, I just need to about 15 balls to give myself in, get myself in, look at the dimensions of the ground'. He's got the game to just go and explode into the boundary hitting mode that wind that we know that he can," he added.India's batting unit has displayed inconsistencies throughout the series, with victories largely coming through individual brilliance rather than collective performance.

Varun Chakravarthy explains how Rajkot pitch helped England defend 171

NEW DELHI. Varun Chakravarthy said that the lack of dew in the second innings of the Rajkot T20I helped England bowlers dominate the Indian batters. On Tuesday, January 28, Suryakumar Yadav's India lost the third T20I by 26 runs as the visitors stayed alive in the series. After being asked to bat first, England put up a healthy score of 171 for the loss of nine wickets.Chasing the challenging target, India finished at 145 for nine. Jamie Overton, Jofra Archer, Mark Wood, Brydon Carse and Adil Rashid did not let the Indian batters dictate terms. Chakravarthy said that the pitch got tougher to bat during India's run-chase as it got slower."The pitch definitely got slower in the second innings. We thought that there might be dew which might set in. But it didn't set in and that definitely played in their favour," Chakravarthy said in the post-match press conference.

Chakravarthy also heaped praise on Rashid and hailed him as a 'legend' after the English spinner finished with figures of 4-0-15-1. "Adil Rashid is a legend and knows how to bowl; he has that control over his speed," Chakravarthy said.From the personal viewpoint, Chakravarthy had a memorable day after he became only the third Indian in Men's T20Is after Kuldeep Yadav and Bhuvneshwar Kumar to pick up multiple five-wicket hauls. Chakravarthy finished with figures of 4-0-24-5. Chakravarthy said that he would keep focussing on being consistent.

"The work doesn't stop because consistency is constant work. Even if I want to bowl a stock ball, I need to keep working on it, need to get 9 out of 10 consistency, and that work is always there. So, right now, my focus is on consistency, and line and length," Chakravarthy added.

The fourth and penultimate T20I of the series is scheduled to take place on Friday, January 31 at the Maharashtra Cricket Association (MCA) Stadium in Pune

Mohammed Shami will regain his rhythm after a couple of more games: Ambati Rayudu

Former India cricketer Ambati Rayudu has backed fast bowler Mohammed Shami to find his rhythm again in a couple of matches after he looked far from his best on his comeback in the third T20I against England in Rajkot.

NEW DELHI. Former India cricketer Ambati Rayudu feels Mohammed Shami will take a couple of more games to find his rhythm back. Shami made his international comeback after a long gap of 14 months in the third T20I against England at Niranjan Shah Stadium, Rajkot. The speedster last represented the country in the ODI World Cup 2023, where he finished as the highest wicket taker with 24 wickets.

However, the star fast bowler looked far from his best on his return as he was out of rhythm and remained wicket-less in his three overs,

giving away 25 runs. Analysing Shami's comeback, Rayudu said that it takes some time for a player to gain confidence about his body after returning from injury and hence Shami wasn't seen at his best.

IND vs ENG 3rd T20I Highlights

"I think his rhythm builds when he runs well during his run-up and comes to the crease at good speed. Today, I couldn't see that much. Having confidence about your body is extremely crucial for a player after injury. Players who've gone through injury will tell you that it takes time after returning. The body remains in good shape but the confidence in one's body to put in the extra efforts comes with time. Hence, I feel Shami will pick up his rhythm after a couple of games," said Rayudu on Star Sports.Former India spinner Piyush Chawla agreed with Rayudu's statements and said that one is bound to have butterflies in his stomach while making a comeback after a long hiatus.

"When you make a comeback to international cricket after so long, you have butterflies in your stomach. No matter, how much you've played in the past when you come back to the team after a long gap of 436 days, there were some nerves there. He didn't look in his usual rhythm, every player takes 1-2 matches. The good thing is that he played a game and bowled three overs and the way he ended his spell. I feel the more he plays, the better he will get," said Chawla.

Meanwhile, India lost the third T20I by 26 runs as they failed to chase down the target of 172. The Men in Blue could only score 145/9 in 20 overs as England bowlers continued to keep a stranglehold on their batting. As a result, they emerged victorious in the game to stay alive in the five-match series which India currently leads by 2-1.

Pashmina Roshan's

Instagram Post Has A Shah Rukh Khan Connection, Did You Get It?

Hrithik Roshan's cousin sister, Pashmina Roshan, is no more unknown to the cinema buffs. She began her acting career with the 2024-released Ishq Vishk Rebound. This is a sequel to the 2003 movie Ishq Vishk, starring Shahid Kapoor in the lead. Coming to the daughter of Hrithik Roshan's uncle Rajesh Roshan, she is extremely active on social media. She recently posted a picture of herself clad in a red coloured sareeTaking to her Instagram handle, Pashmina Roshan dropped a carousel featuring her latest looks in a red-hued pre-draped saree. The 29-year-old actress simply spread the aura of her beauty among her social media community and looked every bit gorgeous. The saree featured a fish-cut, loose-fitted silhouette attached to a piece of the same fabric, which she wrapped around her body as the pallu of the piece.

Pashmina teamed her look with a bralette made of the same shiny fabric. It also featured noodle straps, a board deep neck and no sleeves design. A pair of golden hoop earrings and two diamond bangles accessorised her glam for the day. Coming to her makeup, she was seen flaunting her natural glow alongside fully flushed red cheeks. Glossy lipstick and thin stroke of eyeliner.

However, Pashmina's post also had a quirky note alongside it. She wrote, "Muh toh

band kar lo uncle (please close your mouth, uncle)," followed by a face with a hand over mouth emoji representing her embarrassed look. Many of Pashmina's fans soon began flooding the comment section by showering a lot of love on her picture.

For those unaware, Pashmina had taken admission to Jeff Goldberg Studio in Mumbai after completing college to learn acting. Later she also participated in a theatre play named The Importance of Being Earnest in the year 2019. Apart from this, she is also a trained classical dancer.Previously, in an interview with ANI, Pashmina recalled, "In the initial years, I was very confused if I could be a good actor or not. Poll: Who is the best Bollywood icon of all time? Amitabh Bachchan Shah Rukh Khan Though, I did theatre in school but I was not sure. So, I had applied to different universities in the UK for marketing. I got my visa, rooms were booked and it was summer holiday. I was very depressed. All my friends would go for parties and they would do everything. I used to just sleep in the afternoon." The actress added, "After a lot of rejections, after continuously evaluating myself and taking feedback from family, after many years, I got this opportunity and this film. And I am very grateful for that."

Khushi Kapoor

Calls Character Bani In Loveyapa 'Completely Opposite' To Her: 'Fun Exploring That Side'

Khushi Kapoor and Junaid Khan are all set for their first theatrical release Loveyapa. The rom-com will be released on February 7. However, ahead of the release, the lead actors are seen busy promoting the film on all platforms. Recently, Khushi Kapoor has opened up about her character Bani in the film.Sharing insights into fitting into the shoes of her character, Khushi Kapoor said, "I was sitting quietly in the corner when I first met Advait, and he asked, 'Can you scream? This film is about shouting.' I told him I'd

try. Right after that meeting, I started yelling, and even I was surprised at myself, like, 'Where did this voice come from?' Bani and Gaurav are such bindass, loud characters, completely opposite to us introverts. It was fun exploring that side."

The film is directed by filmmaker Advait Chandan. Talking about him Khushi Kapoor said, "I mean, I had the best experience. I think I immediately just felt seen and heard as an actor. I just felt like he would listen to me and understand me, and he would give us both that space to kind of explore and approach the scene, how we would interpret it, and then kind of give us his notes on how he would want the scene to go."

She added, "So it would kind of give him a fresh perspective and help us understand how the progression of our characters in the scene should be. So, I mean, overall, the whole experience was just the smoothest. And I keep telling him as well, I just think I had the best time shooting this film. It just felt like such a breeze. And I think that affects your performance as well, your environment."

For those unaware, Khushi Kapoor and Junaid Khan's upcoming film Loveyapa is a Hindi remake of the 2022 Tamil movie Love Today.Loveyapa is a fresh take on Gen-Z relationships, blending romance with comedy. The plot revolves around a humorous challenge set by the lead characters' parents, where Gaurav and Baani must exchange their phones for a day to prove their trust before deciding to marry.In addition to Junaid Khan and Khushi Kapoor, the film features a stellar cast including Grusha Kapoor, Ashutosh Rana, Tanvika Parlikar, Kiku Sharda, and Kunj Anand.

Shilpa Shinde Bashes Bigg Boss 18 Makers After Karan Veer Mehra's Win: 'Logon Ko Ullu Bana Sakte Ho'

Karan Veer Mehra's Bigg Boss 18 win has left many disappointed. While some claim that finalist Vivian Dsena should have won Salman Khan's show, others argue that Karan did not deserve to lift the trophy. Recently, television producer Sandeep Sikand also reacted to Karan's victory and claimed that it was not based on audience votes, as fans believed, but on his personality. His statement has reignited debates over the show's credibility, with viewers calling the finale rigged.Therefore, former winner Shilpa Shinde has also bashed the makers of Bigg Boss 18 now. In a statement, the actress alleged that the winner of the controversial reality show is fixed and claimed that makers can no longer befool viewers.

"I don't know, kuch logo ko pata chal gaya ki makers khud hi decide karte hain winner. Khud hi banate hain, apne ghar se uthakar late hain aur khud hi dikhate hain. Toh channel ki jo bhi strategy hai, I think logon ko pata chal gayi hai. Aap ek limit tak logon ko ullu banaa sakte ho, uske baad nahin," Shilpa said.Bigg Boss 18's grand finale was held on January 19. While Karan Veer Mehra emerged as the winner of the show, Vivian Dsena and Rajat Dalal were the first and the second runners-up respectively. Other contestants in the finale were Avinash Mishra, Chum Darang and Eisha Singh.

Following Karan's win, several Bigg Boss 18 contestants were seen expressing disappointment with the audiences' decision. Among others, Arfeen Khan shared a post on her X handle and wrote, "He pinned down my wife, Salman confirmed, he made a mockery of Vivian's child, a fine example for the world of a winner. Rajat Dalal should have won, if not him, Avinash did more than the so-called winner from the beginning. Vivian [Dsena] was honourable. What a world we live in."

Munawar Faruqui's Wife Mehzabeen Coatwala Shares A Romantic Photo On His Birthday, Calls Him 'Hubby'

Munawar Faruqui is celebrating his 33rd birthday on Tuesday, January 28. On this special day, his wife, Mehzabeen Coatwala took to her Instagram stories and sent wishes to the love of her life in a special way. She shared a romantic picture of them from one of their vacations and wrote, "Happy Birthday Hubby", along with a red heart emoji.In the picture, Munawar and Mehzabeen were seen striking a pose on a beach at the time of the sunset. While Munawar sported an all-white attire, Mehzabeen looked prettiest in a red outfit. The two looked lost in each other as Munawar held his wife close and flaunted his charming smile. Check it out here:

Munawar Faruqui and Mehzabeen Coatwala tied the knot on May 26, 2024. It was said to be a close-knit affair which only their family members attended. In the photos from the intimate wedding ceremony that leaked online, the couple was seen cutting a cake together.

Later, a report by Times Now claimed that Hina Khan played cupid for Munawar and Mehzabeen. "Hina Khan introduced Munawar to Mehazabeen. At an event, Hina sent Mehazabeen to Munawar for his makeup. They met for the first time at that event," a source cited by the entertainment portal claimed. It also reported that Hina attended the wedding ceremony as well.

Prior to Mehzabeen, Munawar Faruqui was married to Jasmine, with whom he also has a seven-year-old son named Mikael. While the comedian often shares pictures with his son online, he first opened up about him in Kangana Ranaut's Lock Upp. Later, he also talked about his son with Mannara Chopra while they were in the Bigg Boss 17 house."I have been with someone for the past two years. I was in a marriage in 2017 and in 2020 we got separated. Last year our divorce was finalised. Amid all this, the best thing about my life is my son. He is 5 years old and stays with me," he said.